www.tamsasanket.com
वर्षः 06 || अंक 01 || लखनऊ
बुधवार
01 अप्रैल 2026 || पृष्ठः 04 || मूल्यः ₹ 2
आज़ादी का अमृत महोत्सव
समूह संपादक- डॉ. ओ.पी. मिश्रा
https://epaper.tamsasanket.com

दैनिक तमसा संकेत

डॉ. लोहिया की जन्म भूमि से सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र
लखनऊ व अम्बेडकर नगर से एक साथ प्रकाशित

मौसम
सूर्योदयः 05:57
सूर्यास्तः 06:23
अधिकतमः 36°00
न्यूनतमः 23°00

पेज 03

विशेष समाचार
बढ़ता जा रहा है किडनी खरीद... पेज 02
अंडे पर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी... पेज 04
मीना कुमारी की 54वीं डेथ एनिवर्सरी...

राष्ट्रपति की सुरक्षा में 2500 जवान, 25 हजार श्रद्धालुओं के लिए कोई नहीं

शीतला माता मंदिर में भगदड़

9 की मौत
8 महिलाएं इनमें

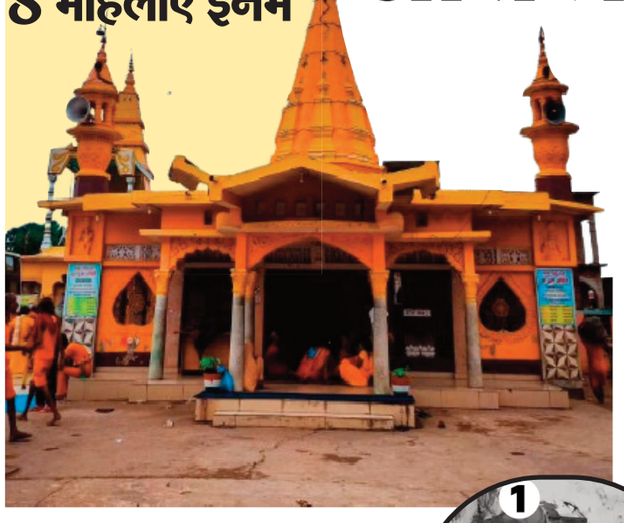

- हादसे के बाद मंदिर परिसर में अफरा-तफरी का माहौल रहा।
- ई-रिक्शा से घायल महिला को अस्पताल लाया गया।
- भगदड़ के बाद मंदिर के पास के तालाब में पूजा सामग्री की दुकानों के सामान गिरे पड़े हैं।

दूसरे श्रद्धालु ने बताया, 'सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया था। मंदिर के अंदर भारी भीड़ थी। पुलिस का जवान अंदर तैनात नहीं था। भीड़ को डायवर्ट करने या दो लाइनों में बांटने की कोई व्यवस्था नहीं थी। मंदिर के पुजारी ही जल्दी-जल्दी दर्शन कर निकलने को कह रहे थे। इस बीच एक महिला को चक्कर आ गया, जिससे वो वहीं गिर पड़ी।

तमसा संकेत, एजेंसी

बिहार में नालंदा जिले में मंगलवार सुबह शीतला माता मंदिर में भगदड़ मच गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। 8 महिलाओं की भीड़ में दबने से मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक पुरुष ने अस्पताल में दम तोड़ा। चैत्र महीने के आखिरी मंगलवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में पहुंचे थे। वहां मेला भी लगा था। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। दर्शन करने की जल्दी में धक्का-मुक्की मच गई। अफरातफरी के बीच कई लोग भीड़ में दब गए। बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। हादसे के बाद मंदिर और मेला को बंद करवा दिया है। आज नालंदा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति शामिल हुईं। उनकी सुरक्षा में 8 जिलों के 2500 जवानों को लगाया गया था, जबकि मंदिर में जुटी 25 हजार की भीड़ के लिए एक भी पुलिस वाले की तैनाती नहीं थी। हादसे के बाद पटना कमिश्नर को बिहार शरीफ भेजा गया है। सीएम ने मुख्य सचिव को जांच के निर्देश दिए हैं। दीपनगर थाने के SHO राजमणि को सस्पेंड कर दिया गया है। सरकार ने मृतकों के आश्रितों को 6 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। वही केंद्र सरकार ने 2 लाख के मुआवजे की घोषणा की है। महिला भक्तों ने बताया कि चैत्र महीने का ये आखिरी मंगलवार है। यहां मेला लगा था। भीड़ ज्यादा हो गई। मंदिर का गर्भगृह भी छोटा है। लोग जल्दी-जल्दी दर्शन करने के लिए एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में थे। कोई लाइन में लगकर पूजा नहीं करना चाह रहा था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आज नालंदा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने नालंदा पहुंचीं। राष्ट्रपति सुबह 11.20 से शाम 4.50 बजे तक नालंदा में रहीं। उनके कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई थी। नालंदा के अलावा जहानाबाद, गया, पटना समेत 8 से अधिक जिलों से ढाई हजार से अधिक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को लगाया गया था। नालंदा के डीएम ने दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मेडिकल सर्विसेज को हाई अलर्ट पर रखा गया था।

40 मिनट बाद पहुंची एंबुलेंस

मंदिर में मौजूद एक श्रद्धालु ने बताया, 'भगदड़ के बाद कई महिलाएं बेहोश पड़ीं थीं। कुछ दर्द से चिल्ला रहीं थीं। लोगों ने पुलिस को खबर की। पहले 2-3 पुलिस वाले पहुंचे। उनके साथ मिलकर श्रद्धालुओं ने घायल महिलाओं को किनारे लिटाया। कई बार एंबुलेंस के लिए फोन किया गया। घटना के करीबब 40 मिनट बाद पहली एंबुलेंस पहुंची और पुलिस के कुछ अफसर भी आए। इसके बाद घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। महिलाओं को उठाते समय ही लग रहा था कि उनमें से कुछ की मौत हो गई है।' भगदड़ के बाद मंदिर के पास के तालाब में पूजा सामग्री की दुकानों के सामान गिरे पड़े हैं।

हादसे से जुड़ी बड़ी बातें

- नालंदा पहुंचे DGP विनय कुमार ने कहा कि मंदिर परिसर में बहुत कमियां हैं। निश्चित तौर पर यहां पुलिस की टीम होनी चाहिए थी। SHO को संस्पेंड किया गया है।
- चैत्र महीने के आखिरी मंगलवार के चलते पटना और आसपास के इलाकों से भी दर्शन के लिए पहुंचे थे। इस वजह भीड़ बहुत बढ़ गई।
- मंदिर परिसर छोटा था। भीड़ को कंट्रोल करने के इंतजाम नहीं थे। लोगों में पहले दर्शन करने की होड़ लग गई।
- लोग कतार में लगने की जगह आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। इससे भगदड़ की स्थिति बन गई। कई लोग भीड़ के नीचे दब गए।
- मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि हादसे के बाद पुलिस और एंबुलेंस को पहुंचने में भी देर हुई।

मंदिर में भगदड़ की टाइमलाइन

9 बजे
- भीड़ बढ़नी शुरू

9:30 बजे
- भगदड़ मची

10:10 बजे
- एंबुलेंस पहुंची
- घायलों को मॉडल अस्पताल भेजा गया
- 9 लोगों की मौत

11 बजे
- पटना कमिश्नर मौके पर पहुंचे

12 बजे
- मुआवजे का ऐलान
- बिहारः 6 लाख, केंद्रः 2 लाख मुआवजा

1 बजे
- थानेदार दीपनगर सस्पेंड

1:20 बजे
- डीएम कौशल कुमार मौके पर पहुंचे

सीएम ममता के गढ़ में सुवेंदु की ललकार

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में चुनावी पारा अपने चरम पर है। इस बार कोलकाता की भवानीपुर विधानसभा सीट एक ऐसे सियासी रणक्षेत्र में तब्दील होने जा रही है, जिसकी धमक पूरे देश में सुनाई देगी। इस हाई-वोल्टेज ड्रामे की शुरुआत 2 अप्रैल को होगी। कयास लगाया जा रहा है कि इस दिन भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी यहां से अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस दौरान पार्टी की ओर से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी भी है। सुवेंदु अधिकारी के इस जुलूस में खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होकर माहौल को गरमाएंगे। भाजपा की रणनीति ममता बनर्जी को उन्हीं के घर में घेरने की है। हालांकि, 'दीदी' भी पीछे रहने वाली नहीं हैं। सुवेंदु के ठीक छह दिन बाद यानी 8 अप्रैल को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी नामांकन पर्चा दाखिल करेंगी। इस दौरान 'दीदी' अपने कालीघाट स्थित आवास से पैदल ही पर्चा भरने के लिए निकलेंगी।

ईसी ऑफिस के बाहर भाजपा-टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प

ममता का आरोप- भाजपा ने बंगाल में अवैध वोटरों के नाम जोड़ने की कोशिश की

- कोलकाता में टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया।

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली/गुवाहाटी/कोलकाता/चेन्नई। कोलकाता में चुनाव आयोग ऑफिस (ECO) के बाहर मंगलवार को भाजपा और TMC कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। पुलिस के अनुसार, TMC समर्थित बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) का एक ग्रुप वोटर लिस्ट में हेरफेर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था। इस दौरान उन्होंने सुरक्षाबलों पर पथराव किया। इससे वहां खड़े वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। बाद में भाजपा के कार्यकर्ता भी वहां झंडा लेकर पहुंच गए। इसके बाद TMC प्रदर्शनकारियों की पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं से झड़प हो गई। पुलिस ने बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हल्का बल का प्रयोग किया गया। इधर बंगाल की CM ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि BJP बिहार, उत्तर प्रदेश के अवैध वोटरों को बंगाल के वोटर लिस्ट में शामिल करने की कोशिश कर रही है।

>> (शेष पेज 04 पर)

कांग्रेस अफवाह फैला रही : मोदी

पेट्रोल पंपों पर भीड़ जुटाकर व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश, देश में स्थिति कंट्रोल में है

5100 करोड़ की लागत से अहमदाबाद-धोलेरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन

शिलान्यास

मोदी ने कहा कि मुश्किल समय में भी कांग्रेस जनता को भड़काने और अफवाह फैलाने में लगी है। उनका आरोप है कि कांग्रेस सियासी लाभ के लिए हालात बिगाड़ने और पेट्रोल पंपों पर भीड़ जुटाकर अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रही है।

तमसा संकेत, एजेंसी

अहमदाबाद। पीएम मोदी मंगलवार को गुजरात के दौरे पर थे। उन्होंने वाव-थराड में 20 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में जंग की वजह एनर्जी संकट बढ़ रहा है। ऐसे संकट में भी भारत ने हालात को नियंत्रण में बनाए रखा है। इससे पहले उन्होंने साणंद में केयन्स सेमीकॉन के आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट (OSAT) का और गांधीनगर में सम्राट सम्प्रति म्यूजियम का उद्घाटन किया। यहां पीएम ने कहा, 'हमने कोरोना के समय ही तय कर लिया था।

>> (शेष पेज 04 पर)

पीएम बोले- यहां बने मॉड्यूल अमेरिका भेजे जाएंगे

मुझे पता चला है कि यहां वर्तमान में निर्मित उत्पादों का एक बड़ा बैच एक्सपोर्ट के लिए पहले ही बुक हो चुका है। साणंद में उत्पादित मॉड्यूल अमेरिकी कंपनियों को आपूर्ति किए जाएंगे, जिससे दुनिया भर के उद्योगों को बिजली आपूर्ति में मदद मिलेगी। 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' पहल का प्रभाव विश्व के हर कोने में महसूस किया जाएगा। क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन भी शुरू किया गया है।

फास्ट न्यूज

वैश्विक संघर्षों पर दलाई लामा ने जताई चिंता

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी ईरान-इस्राइल, अमेरिका और यूरोप में रूस-यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। साथ ही उन्होंने पाम संडे के मौके पर पोप की ओर से की गई शांति की अपील समर्थन किया है। दलाई लामा ने कहा कि हथियारों को डाल देने और हिंसा को पूरी तरह छोड़ देने की यह पुकार उनके विचारों से गहराई को छू गई।

कई जवानों को समय पर वेतन-भत्ते नहीं मिले

नई दिल्ली। कम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया (CAG) की डिफेंस पर रिपोर्ट सोमवार को संसद में पेश की गई। इसमें कई मिलिट्री अस्पतालों के रखरखाव में कमी की ओर भी इशारा किया गया है। यह भी बताया गया है कि काफी संख्या में सेना के जवानों को उनके वेतन-भत्ते समय पर और सही तरीके से नहीं मिले। रिपोर्ट के मुताबिक, सेना के निर्माण कार्यों से जुड़े साइट रिकॉर्ड्स ठीक से नहीं रखे गए। इससे काम की क्वालिटी और ठेकेदार की जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हुआ। ऑडिट ने सिफारिश की है कि रक्षा मंत्रालय साइट रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करे। साइट रिकॉर्ड्स में काम की प्रगति, मेटेरियल और टेस्ट रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी रिकॉर्ड होती हैं।

बेंगलुरु में इंजीनियर कपल ने सुसाइड किया

बेंगलुरु। बेंगलुरु के कोथनूर इलाके के अपार्टमेंट में एक इंजीनियर कपल के सुसाइड का मामला सामने आया है। पहले पति का शव फ्लैट के बंद कमरे में मिला। कई बार दरवाजा खटखटाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला तो पत्नी ने सिक्योरिटी और पड़ोसियों को बुलाया। इसके कुछ ही मिनट बाद पत्नी फ्लैट से बाहर निकलीं और उसी अपार्टमेंट की 17वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी।

पिता से विवाद पर बच्चे को पैर पकड़कर पटका

सिर लोहे की रॉड पर मारा, हालत गंभीर, मुंबई की घटना

तमसा संकेत, एजेंसी

मुंबई। महाराष्ट्र के मुंबई से सटे वसई इलाके में एक व्यक्ति ने पिता से मामूली विवाद का गुस्सा उसके 4 साल के बच्चे पर उतार दिया। आरोपी ने बच्चे को ऑटो-रिक्शा से बाहर खींचकर सड़क पर पटक दिया और उसका सिर लोहे की रॉड पर भी मारा। पुलिस के मुताबिक यह घटना वसई की एक हाउसिंग सोसायटी में हुई। पूरी घटना सोसायटी में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो मंगलवार को सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले उसका बच्चे के पिता से किसी मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी के बाद आरोपी ने बदला लेने की नीयत से यह कदम उठाया। CCTV फुटेज में दिखाई दे रहा है कि 4 साल का

विग्नेश (पीली टी-शर्ट में) सोसायटी परिसर में खड़े एक ऑटो-रिक्शा में अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान आरोपी संदीप पवार वहां पहुंचा। आरोपी ने अचानक बच्चे को उसके पैरों से पकड़कर ऑटो से बाहर खींच लिया। इसके बाद उसने मासूम को जोर से सड़क पर पटक दिया। आरोपी ने बच्चे का सिर पास में मौजूद लोहे की रॉड पर दे मारा और फिर दोबारा जमीन पर फेंक दिया।

अमेरिका किसी देश की मदद नहीं करेगा : ट्रम्प

हमसे तेल खरीदो, नहीं तो हिम्मत दिखाओ और होर्मुज जाकर ले लो

तमसा संकेत, एजेंसी

तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार को कहा कि अब अमेरिका किसी देश की मदद नहीं करेगा। देशों को खुद ही अपने हालात संभालने होंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ब्रिटेन जैसे देश जो होर्मुज स्ट्रेट से फ्यूल नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें अमेरिका से तेल खरीदना चाहिए क्योंकि अमेरिका के पास इसकी कोई कमी नहीं है। हमले के बाद डिपो में रखे हथियारों में विस्फोट होने से कई धमाके हुए और इलाके में आग के बड़े गुबार उठे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भी सोशल मीडिया पर धमाकों का एक वीडियो शेयर किया है। अगर इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है या केबल्स को नुकसान पहुंचता है, तो भारत समेत पूरी दुनिया में इंटरनेट की स्पीड स्लो हो सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है

कि यह इलाका सिर्फ एनर्जी चोकपॉइंट नहीं, बल्कि एक डिजिटल चोकपॉइंट भी है। अक्सर लोगों को लगता है कि इंटरनेट सैटेलाइट के जरिए चलता है, लेकिन हकीकत अलग है। दुनिया का करीब 95 से 97% डेटा फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए ट्रांसफर होता है। ईरान ने उन खबरों को पूरी तरह से गलत बताया है जिनमें कहा गया था कि उसने तुर्किये पर मिसाइलें दागी हैं। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने कहा कि ये दावे पूरी तरह बेबुनियाद हैं। उन्होंने तुर्किये के विदेश मंत्री हाकन फिदान से फोन पर बात करके कहा कि अगर कोई आरोप है तो दोनों देश मिलकर इसकी जांच कर सकते हैं।

>> (शेष पेज 04 पर)

अमेरिका ने ईरान में हथियार डिपो पर एयरस्ट्राइक की

अमेरिका ने ईरान के इस्फहान शहर में एक बड़े हथियार डिपो पर एयरस्ट्राइक की है। वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट के मुताबिक, यह हमला सोमवार रात को किया गया। इसके लिए 2000 पाउंड के बंकर-बस्टर बमों का इस्तेमाल हुआ। रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा गया है बंकर-बस्टर बमों का इस्तेमाल मजबूत और भूमिगत ठिकानों को तबाह करने के लिए किया जाता है।

दुनियाभर में इंटरनेट ठप होने का खतरा, होर्मुज में बिछीं केबल्स को नुकसान की आशंका

अमेरिका-इजराइल और ईरान जंग के चलते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज प्रभावित होने से दुनियाभर में एनर्जी क्राइसिस के बाद अब इंटरनेट ठप होने का खतरा है। इसकी वजह यह है कि होर्मुज रूट से न केवल दुनिया का 20% कच्चा तेल और 25% LNG गुजरती है, बल्कि इस रास्ते के नीचे इंटरनेट केबल्स भी बिछीं हैं।

ट्रम्प ने कहा कि अगर देश चाहें, तो हिम्मत दिखाएं और खुद होर्मुज स्ट्रेट जाकर तेल ले लें। अमेरिका उनकी मदद के लिए नहीं आएगा, जैसे वे अमेरिका की मदद के लिए नहीं आए। अपने बयान में उन्होंने यह भी कहा कि ईरान काफी हद तक कमजोर हो चुका है और सबसे मुश्किल काम पहले ही पूरा हो गया है।

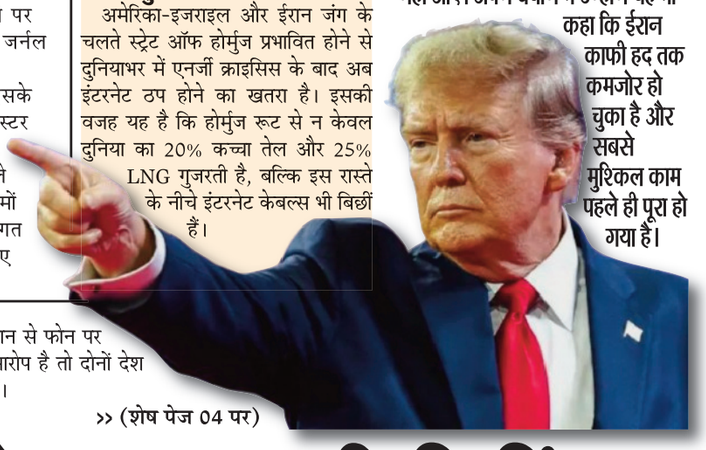

प्रभावित : जंग से होर्मुज में बिछीं केबल्स को नुकसान की आशंका, समुद्र में 97% ग्लोबल डेटा

भारत समेत दुनियाभर में इंटरनेट ठप होने का खतरा

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। अमेरिका-इजराइल और ईरान जंग के चलते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज प्रभावित होने से दुनियाभर में एनर्जी क्राइसिस के बाद अब इंटरनेट ठप होने का खतरा है। इसकी वजह यह है कि होर्मुज रूट से न केवल दुनिया का 20% कच्चा तेल और 25% LNG गुजरती है, बल्कि इस रास्ते के नीचे इंटरनेट केबल्स भी बिछीं हैं। अगर इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है या केबल्स को नुकसान पहुंचता है, तो भारत समेत पूरी दुनिया में इंटरनेट की स्पीड स्लो हो सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह इलाका सिर्फ एनर्जी चोकपॉइंट नहीं, बल्कि एक डिजिटल चोकपॉइंट भी है। भारत की डिजिटल इकोनॉमी काफी हद तक इन समुद्री रूट्स पर निर्भर है।

>> (शेष पेज 04 पर)

समुद्र के नीचे से गुजरता है 97% ग्लोबल डेटा

अक्सर लोगों को लगता है कि इंटरनेट सैटेलाइट के जरिए चलता है, लेकिन हकीकत अलग है। दुनिया का करीब 95 से 97% डेटा फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए ट्रांसफर होता है। ये केबल्स समुद्र के नीचे बिछी होती हैं। भारत को यूरोप, अफ्रीका और पश्चिम एशिया से जोड़ने वाली मुख्य केबल्स इसी रूट के पास से गुजरती हैं। इसमें SEA-ME-WE, AAE-1 और EIG जैसे बड़े केबल सिस्टम शामिल हैं।

भारत का ज्यादातर इंटरनेशनल इंटरनेट बैंडविड्थ अरब सागर और खाड़ी क्षेत्र से होकर आता है।

क्या पूरी तरह बंद हो जाएगा इंटरनेट?

इंटरनेट का डिजाइन इस तरह बनाया गया है कि एक रास्ता बंद होने पर ट्रैफिक दूसरे रास्ते (री-रूटिंग) पर चला जाता है। इसलिए 'टोटल ब्लैकआउट' यानी पूरी तरह इंटरनेट बंद होने की संभावना कम है। हालांकि, री-रूटिंग की वजह से वैकल्पिक रास्तों पर लोड बढ़ जाएगा, जिससे स्पीड बहुत कम हो जाएगी। शेयर बाजार और हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग जैसे सेक्टर्स, जहां मिलीसेकंड का महत्व होता है। केबल कटने की स्थिति में कंपनियों को भारी नुकसान हो सकता है, जिससे सर्विस एग्रीमेंट्स (SLA) टूटने और पेनाल्टी लगने का डर है। इसके अलावा, खाड़ी देशों से आने वाली रेमिटेंस (पैसा भेजना) और SWIFT जैसे बैंकिंग ट्रांजेक्शन भी धीमे पड़ सकते हैं।

नए ऑप्शन पर निवेश कर रहा भारत

इस खतरे को देखते हुए भारत समेत कई देश अब वैकल्पिक रास्तों पर निवेश कर रहे हैं। इलॉन मस्क की स्टारलिंक जैसी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज बैकअप के तौर पर देखी जा रही हैं। भविष्य में ऐसी केबल्स बिछाने की योजना है जो संवेदनशील क्षेत्रों को बायपास कर सकें। फिलहाल, होर्मुज में बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव तेल की कीमतों से ज्यादा डिजिटल दुनिया की चिंता बढ़ा रहा है।

सूरत की बिल्डिंग में आग, 5 की मौत

एक बच्चा शामिल, घर में रखा था 8 टन साड़ियों का स्टॉक

हादसा

तमसा संकेत, एजेंसी

सूरत। गुजरात के सूरत में एक मकान में मंगलवार दोपहर को आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पड़ोसियों से मिली जानकारी के मुताबिक, शहर के लिंबायत इलाके का यह मकान एक व्यापारी का है, जिसमें करीब 8 टन साड़ियों का स्टॉक रखा हुआ था। इससे घर में पैदल चलने तक की जगह नहीं बची थी। इसी के चलते आग इतनी तेजी से भड़की। किसी को बचने का मौका नहीं मिला। मरने वालों में एक बच्चे समेत 4 महिलाएं शामिल हैं।

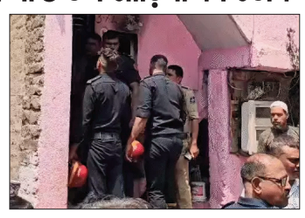

- घर से जले हुई साड़ियां निकालते स्थानीय लोग।
- जोरदार धमाके से घर का दरवाजा उखड़कर सामने वाली दीवार से जा टकराया।

सम्पादकीय

ट्रंप पर अंकुश लगाना जरूरी

शा ईरान पर इजरायल और अमेरिका को युद्ध छेड़े 31 दिन पूरे हो चुके हैं और इस एक महीने में ईरान समेत पूरी दुनिया को बड़ी तबाही की राह पर धकेला जा चुका है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम से अकल्पनीय त्रासदी कायम करने वाले अमेरिका ने परमाणु हथियार रोकने के नाम पर ही जंग का यह खेल शुरु किया, लेकिन अब उनकी असली नीयत सामने आ गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह 'ईरान का तेल अपने कब्ज़े में लेना' चाहते हैं और खर्ग द्वीप पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। गौरतलब है कि खर्ग द्वीप ईरान की तेल निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, यहां से 90 प्रतिशत तक तेल निर्यात होता है। और इस द्वीप पर कब्जा करने के लिए हजारों सैनिकों को जमीन पर उतारने की तैयारी अमेरिका ने की है, यह बात वॉशिंगटन पोस्ट में छपी एक खबर से जाहिर हुई है। हालांकि ट्रंप अब खुलकर अपनी कपटी नीयत का इजहार भी कर रहे हैं। ट्रंप ने फ़ाइनेंशियल टाइम्स से साफ कहा है कि वे ईरान के तेल पर कब्जा करना चाहते हैं, इसके बाद कोई संदेह बाकी नहीं रह जाता कि परमाणु हथियार केवल एक बहाना थे। मगर सवाल वही है कि कब तक विश्व ट्रंप या अमेरिका के छलावे भरे दावों पर यकीन करेगा। अंग्रेजी भाषा के वर्चस्व और हॉलीवुड में बनी फिल्मों के जरिए पूरी दुनिया में एक भ्रम अमेरिका ने खड़ा किया है कि वह लोकतंत्र और विश्व शांति का सबसे बड़ा रक्षक है, जबकि रूस, क्यूबा, चीन जैसे साम्यवादी देश या ईरान, अफगानिस्तान जैसे देश दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। अमेरिका के रचे इस दृश्यम का ऐसा असर हुआ है कि दुनिया उसकी परोसे नैरेटिव को ही सच मानती है, और भूल जाती है कि हर तस्वीर का दूसरा पहलू भी होता है। अब ट्रंप ने जो 15 सूत्रीय प्रस्ताव युद्धविराम के लिए दिए थे ये शर्तें बता रही हैं कि अमेरिका ईरान को अपनी शर्तों पर चलाना चाहता है, वेनेजुएला में पहले ही उसने राष्ट्रपति का अपहरण किया और अब वह क्यूबा में ऐसा ही करने की धमकी दे रहा है। इसके बाद अगली बारी किस देश की होगी, कहा नहीं जा सकता। अमेरिका की दूसरे देशों में हस्तक्षेप की नीति तो शुरु से रही है, लेकिन ट्रंप इसे पूरी निर्लज्जता से जाहिर भी कर रहे हैं। रविवार को एयर फ़ोर्स वन पर ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि 'ईमानदारी से कहूं, तो मेरी पसंदीदा चीज़ है ईरान का तेल लेना। लेकिन अमेरिका में कुछ लोग कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। वे लोग बेवकूफ़ हैं।' वहीं ट्रंप ने यह भी कहा कि 'अगर आप देखें, तो वहां पहले ही शासन परिवर्तन हो चुका है। पहला शासन पूरी तरह ख़त्म हो गया, नष्ट हो गया, वे सभी मारे जा चुके हैं। दूसरा शासन भी लगभग ख़त्म हो चुका है और अब तीसरे शासन में हम ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं, जिनसे पहले कभी किसी ने बात नहीं की। यह बिल्कुल अलग समूह है, इसलिए मैं इसे शासन परिवर्तन मानता हूं। ट्रंप ने कहा, 'जो शासन बहुत ख़राब था, बहुत बुरा था, दूसरा जिसे नियुक्त किया गया था, वे सभी अब ख़त्म हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं। केवल एक व्यक्ति बचा है, जिसमें शायद थोड़ी जान बाक़ी है।' ट्रंप ने आगे कहा, 'ईरान के साथ कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हम उनसे बातचीत करते हैं और फिर हमें उन्हें बम से उड़ाना पड़ता है।' हैरानी की बात है कि किस तरह किसी देश की निजता और संप्रभुता का न केवल मखौल ट्रंप उड़ा रहे हैं, बल्कि शीर्ष नेताओं की हत्या जैसे अंतरराष्ट्रीय अपराध को जायज भी ठहरा रहे हैं। अगर कोई देश इसी तरह की बात अमेरिका के लिए करे तो क्या उसे बर्दाश्त किया जाएगा, शायद नहीं। अंतरराष्ट्रीय बिरादरी पहले ही व्हाइट हाउस पर हमले या अमेरिकी राष्ट्रपति समेत शीर्ष नेताओं की हत्या के विचार को आतंकवाद करार देते हुए उस देश या व्यक्ति पर आपराधिक मुकदमा चलाने की बात करने लगेगी। तो फिर ट्रंप के ऐसे बयानों पर व्यापक विरोध क्यों नहीं हो रहा, यह विचारणीय है। इस समय स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज जैसे नेताओं की सख्त जरूरत है, जो न केवल ईरान पर हमले को खुलकर गलत बता रहे हैं, बल्कि अमेरिका का साथ देने से साफ इंकार भी कर चुके हैं। ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को बहाना बनाकर उसके प्राकृतिक संसाधन पर कब्जे का बेशर्म इजहार ट्रंप ने किया है, तो फिर प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न भारत जैसे बाकी देशों को भी सावधान हो जाना चाहिए।

बढ़ता जा रहा है किडनी खरीद फरोक्त का धंदा, कानपुर में 60 लाख में हुई किडनी की डील

> बताया जाता है कि सोमवार को पुलिस की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग से एसीएमओ डॉ। रमित रस्तोगी और कल्याणपुर सीएचसी प्रभारी डॉ। राजेश सिंह व टीम के अन्य अधिकारियों ने तीनों अस्पतालों का निरीक्षण किया।

कानपुर में किडनी रैकेट मामले हाल ही में अख़बारों की सुर्खिया बनी है । हालिया कांड में जिन तीन प्राइवेट अस्पतालों का नाम सामने आ रहा है, उनमें से एक के पास रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। पूरा अस्पताल ही अवैध तरीके से संचालित हो रहा है। इसकी जानकारी खुद स्वास्थ्य विभाग को तब हुई जब मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम पुलिस की टीम के साथ निरीक्षण करने पहुंची। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, मामले में 50 से ज्यादा अस्पताल रडार पर हैं जिनकी जांच की जा रही है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम संयुक्त रूप से देर रात तक जांच में जुटी रही। अधिकारियों के अनुसार, इस मामले कई वरिष्ठ डॉक्टरों से भी पूछताछ की जा रही है, कुछ चिकित्सक कई बड़ी संस्थाओं से भी जुड़े हैं। एसीएमओ ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ऐसे डॉक्टरों की भी तलाश कर रही हैं जो सर्जन या नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। सूत्रों के अनुसार मामले में जिन अस्पतालों के नाम सामने आ रहे हैं, उनके यहां छोटे ऑपरेशन की भी सुविधा नहीं है। इन अस्पतालों में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बाहर से डॉक्टर बुलाए जाते हैं। चिकित्साधिकारियों के अनुसार ऐसे डॉक्टरों से भी पूछताछ की जाएगी। कानपुर के बड़े किडनी रैकेट का भंडाफोड़ होने के बाद एक बार फिर किडनी की खरीद-फरोख्त और अंग प्रत्यारोपण की व्यवस्था पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। डाक्टर कहते हैं कि देश में किडनी के मरीजों की संख्या अधिक और अंगदान कम होने के कारण किडनी खरीद-फरोख्त का रैकेट चल रहा है। इसको लेकर कड़े कानून होने के बावजूद पहले की तुलना में अब अधिक रकम पर किडनी की खरीद-बिक्री होती है। लिहाजा डाक्टर कैडेवर डोनर (ब्रेन डेड होने के बाद अंगदान) किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा बढ़ाने की जरूरत बता रहे हैं। एम्स के नेफ्रोलाजी विभाग के विभागाध्यक्ष डा। एसके अग्रवाल ने कहा कि इससे पहले भी देश के विभिन्न हिस्सों में किडनी रैकेट के मामले सामने आते रहते हैं। इसका कारण यह है कि करीब चार लाख मरीजों को किडनी प्रत्यारोपण की जरूरत है, जबकि हर साल सिर्फ करीब दस हजार मरीजों की ही किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी हो पाती है। इसमें भी कैडेवर डोनर प्रत्यारोपण बहुत कम होता है। इसका कारण यह है कि डोनर उपलब्ध नहीं हो पाते। जीवित व्यक्ति के किडनी दान करने के लिए भी स्वस्थ होना जरूरी है। ज्यादातर मरीजों के बुजुर्ग माता-पिता स्वास्थ्य कारणों से किडनी दान नहीं कर पाते। भाई-बहन और परिवार के अन्य सदस्य जल्दी किडनी दान नहीं करना चाहते। पुरुष मरीजों को ज्यादातर पत्नियां ही किडनी देती हैं। मरीज महिला हो तो डोनर की समस्या और बढ़ जाती है। इस वजह से डोनर मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में किसी गैर व्यक्ति या महिला को रिश्तेदार या पत्नी बताकर डोनर के रूप में लाया जाता है। इसका सत्यापन करना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि फर्जी पहचान पत्र भी आसानी से बन जाते हैं। इस रैकेट से मरीज की भी पूरी मिलीभगत होती है। डाक्टर बताते हैं कि देश में सड़क हादसे में हर साल लगभग डेढ़ लाख लोगों की मौत होती है। इनमें से ज्यादातर लोगों का अंगदान संभव हो सकता है। लेकिन, जागरूकता के अभाव में अंगदान बहुत कम होता है। स्थिति यह है कि एक लाख की आबादी पर भारत में एक व्यक्ति भी यहां अंगदान नहीं करता, जबकि स्पेन में एक लाख की आबादी में 48 लोग अंगदान करते हैं। डाक्टर बताते हैं कि कभी एक से दो लाख रुपये में किडनी बिकती थी, जबकि आज एक आम मरीज भी 20 से 25 लाख रुपये तक देने के लिए तैयार रहता है। हालांकि, इस रैकेट में गिरफ्तार आरोपित ने खुद कुबूल किया है कि वे मरीजों से प्रति किडनी 40 से 70 लाख रुपये तक वसूलते थे। दुर्भाग्य की बात यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर कई परिवार के लोग भी पैसे के लिए किडनी बेचने के लिए राजी हो जाते हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के यूरोलाजी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डा। राजीव सूद के अनुसार किडनी रैकेट में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। साथ ही सड़क हादसों में जान गंवाने वाले लोगों का अंगदान बढ़ाना जरूरी है। अभी अंगदान के लिए लोगों में जागरूकता का अभाव है। इसलिए बहुत कम लोग अंगदान करते हैं। स्पेन में अंगदान अनिवार्य है। इस तरह कानून यहां भी होना चाहिए। हाल की एक घटना के अनुसार बाईस वर्षीय अमोन किप्रुटो मेली ने सोचा था कि अपनी किडनी बेचकर वह एक नई और बेहतर जिंदगी शुरू कर सकेगा। कोविड महामारी के बाद पश्चिमी केन्या के एक गांव में उसका जीवन कठिन हो गया था। वह स्थिर आय कमाने के लिए संघर्ष कर रहा था और एक नौकरी से दूसरी नौकरी बदलता रहा - कभी कार डीलर पर, कभी निर्माण स्थल पर, कभी अन्य जगहों पर। फिर एक दिन, एक दोस्त ने उसे 6,000 डॉलर (5,300 यूरो) कमाने का एक आसान और तेज़ तरीका बताया। एमोन ने कहा, ₹उसने मुझसे कहा कि अपनी किडनी बेचना एक अच्छा सौदा होगा।₹ यह किस्मत का एक अच्छा मौका लगा, लेकिन इसने उसे शोषण, हताशा और पछतावे के एक अंधेरे जाल में फंसा दिया।यह रिपोर्ट जर्मन मीडिया आउटलेट्स डेर स्पीगल , जेडडीएफ और डीडब्ल्यू द्वारा महीनों तक चले एक संयुक्त जांच का परिणाम है , जिन्होंने मिलकर अंग विक्रेताओं और खरीदारों के रास्तों का पता लगाया, दस्तावेजों का विश्लेषण किया, मुखबिरों और चिकित्सा पेशेवरों से बात की, और यह उजागर किया कि कैसे एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क - केन्या के एक अस्पताल से लेकर जर्मनी से अंग प्राप्तकर्ताओं को आकर्षित करने वाली एक गुप्त एजेंसी तक फैला हुआ - दोनों छोर पर कमजोर लोगों का शोषण करता है: पैसे के लिए बेताब युवा और जीवन रक्षक अंग के लिए बेताब बुजुर्ग। पश्चिमी केन्या में अपने घर में अमोन किप्रुटो मेली और उनकी मां लेआ मेट्टो अमोन जैसे छोटे बच्चों के माध्यम से पैसा कमा रहे हैं।

■ अशोक भाटिया

यह समन्वित रणनीति...

ललित गर्ग

माओवादी मुक्ति से शांति एवं संतुलन की नई संभावनाएं

भारत जैसे विशाल, विविधतापूर्ण और लोकतांत्रिक राष्ट्र के सामने आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां हमेशा से बहुआयामी रही हैं। इन चुनौतियों में नक्सलवाद या माओवादी हिंसा एक ऐसी समस्या रही, जिसने दशकों तक देश की आंतरिक शांति, विकास और सुशासन को गंभीर रूप से प्रभावित किया। विशेषकर छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार और आंध्र प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में माओवादी गतिविधियों ने न केवल विकास को अवरुद्ध किया, बल्कि हजारों निर्दोष नागरिकों और सुरक्षाकर्मियों की जान भी ली। लेकिन आज जब बस्तर जैसे माओवादी गढ़ से 25 लाख के इनामी सरगना पापा राव का अपने साथियों सहित आत्मसमर्पण करना एक निर्णायक मोड़ के रूप में सामने आया है, तब यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत माओवादी मुक्ति की ऐतिहासिक दहलीज पर खड़ा है। नक्सलवाद की जड़ें सामाजिक-आर्थिक असमानता, उपेक्षा और शोषण में रही हैं, लेकिन समय के साथ यह आंदोलन अपने मूल उद्देश्यों से भटककर एक हिंसक और विध्वंसकारी विचारधारा में बदल गया। माओवादी संगठन न केवल विकास कार्यों में बाधा डालते रहे, बल्कि उन्होंने स्थानीय लोगों को भय और हिंसा के माध्यम से नियंत्रित किया। स्कूल, सड़क, स्वास्थ्य केंद्र जैसे बुनियादी ढांचे को नष्ट करना उनकी रणनीति का हिस्सा बन गया था। इससे यह स्पष्ट हो गया कि यह आंदोलन अब जनहित का नहीं, बल्कि सत्ता और नियंत्रण का माध्यम बन चुका है। भारत सरकार द्वारा 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद/माओवाद से मुक्त करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, वह अब लगभग अपनी अंतिम अवस्था में पहुंचता दिखाई दे रहा है। पिछले एक दशक में 10,000 से अधिक माओवादियों के आत्मसमर्पण, सुरक्षा बलों की आक्रामक एवं रणनीतिक कार्रवाई तथा प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से हुए विकास कार्यों ने माओवादी आंदोलन की जड़ों को कमजोर कर दिया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में माओवादी हिंसा की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। विशेष रूप से शीर्ष नेतृत्व के आत्मसमर्पण, जैसे दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्यों के सरेंडर ने संगठन को नेतृत्वहीन कर दिया, जिससे माओवादी संरचना भीतर से कमजोर पड़ गई। इस सफलता के पीछे सरकार की बहुआयामी रणनीति रही, जिसमें केवल सैन्य-पुलिस कार्रवाई ही नहीं, बल्कि विकास, पुनर्वास और प्रशासनिक पहुंच को भी समान महत्व दिया गया। रेड कॉरिडोर क्षेत्रों में सड़कों और पुलों का निर्माण, मोबाइल टावरों के माध्यम से 4जी नेटवर्क का विस्तार, स्कूलों और आईटीआई संस्थानों की स्थापना ने इन क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ा। वहीं 'फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशनों' की रणनीति के माध्यम से सुरक्षा बलों ने माओवादियों के गढ़ों में घुसकर निर्णायक कार्रवाई की। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के लिए पुनर्वास नीति के तहत आर्थिक सहायता, रोजगार और समाज में पुनर्स्थापना की व्यवस्था ने भी माओवादी कैडर को हथियार छोड़ने के लिए प्रेरित किया। यह समन्वित रणनीति, दूरदर्शिता और दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिणाम है कि देश आज नक्सलवाद के अंत के ऐतिहासिक चरण के निकट खड़ा दिखाई दे रहा है। निश्चित ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए बहुआयामी और दृढ़ रणनीति अपनाई। गृहमंत्री अमित शाह की सूझबूझ और स्पष्ट दृष्टिकोण ने इस अभियान को एक नई दिशा दी। सरकार ने एक ओर जहां सुरक्षा बलों को आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रशिक्षण और संसाधनों से सशक्त किया, वहीं दूसरी ओर विकास योजनाओं को भी गति दी। 'सुरक्षा और विकास' के इस दोहरे दृष्टिकोण ने माओवादी प्रभाव वाले क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन की नींव रखी। पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षाबलों द्वारा चलाए गए सघन अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को गहराई से कमजोर किया है। बस्तर, जो कभी माओवादियों का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था, वहां आज आत्मसमर्पण की घटनाएं बढ़ रही हैं। पापा राव जैसे शीर्ष माओवादी नेता का आत्मसमर्पण इस बात का संकेत है कि माओवादी संगठन अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह केवल एक व्यक्ति का आत्मसमर्पण नहीं, बल्कि एक विचारधारा के पतन का प्रतीक है। माओवादी मुक्ति का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि देश के उन क्षेत्रों में शांति और स्थिरता स्थापित होगी, जो लंबे समय से हिंसा की चपेट में रहे हैं। जब बंदूकें खामोश होंगी, तब विकास की आवाज बुलंद होगी। सड़कें बनेंगी, स्कूल खुलेंगे, अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ेंगी और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों के जीवन में सुरक्षा और विश्वास का संचार होगा। आदिवासी और ग्रामीण समुदाय, जो अब तक भय और असुरक्षा में जी रहे थे, वे अब अपने अधिकारों और अवसरों का पूर्ण लाभ उठा सकेंगे। इसके साथ ही, माओवादी हिंसा के समाप्त होने से भारत की आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी। जब देश के भीतर शांति होगी, तब ही बाहरी खतरों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सकता है। नक्सलवाद जैसी समस्याएं अक्सर विदेशी शक्तियों और असामाजिक तत्वों के लिए भी अवसर प्रदान करती हैं।

विकसित भारत...

डा.वेदप्रकाश

विकसित भारत के लिए व्यक्ति निर्माण आवश्यक

विकसित भारत एक संकल्प और विचार है जिसमें एक नागरिक के नाते हम सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। विकास की संकल्पना का मूल व्यक्ति ही है। एक इकाई के रूप में यह व्यक्ति भिन्न-भिन्न भूमिकाओं में विकास की विभिन्न संकल्पनाओं को साकार करता है। आज जब राष्ट्रीय और वैश्विक फलक पर विभिन्न अवसर एवं चुनौतियां सामने हैं तब यह आवश्यक है कि विकसित भारत के लिए एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण हो जो भारत भाव से समन्वित हो। ध्यान रहे मन, कर्म, वचन से मातृभूमि को समर्पित व्यक्ति ही विकसित भारत के संकल्प में निर्णायक भूमिका अदा करेगा। महर्षि अरविंद ने कहा था- हमें उतना सामर्थ्यवान बनना होगा, जितना हम पहले कभी नहीं थे। हमें कुछ आदतें बदलनी होंगी, एक नए हृदय के साथ अपने को फिर से जाग्रत करना होगा। ध्यान रहे हमारा सामर्थ्य निर्माण और नवजागरण राष्ट्रहित में हो। क्योंकि निहित स्वार्थों की अवधि व दृष्टि बहुत संकुचित होती है, उससे राष्ट्रीय सरोकार सिद्ध नहीं होंगे। वेदों में भूमि को माता और समूची वसुधा को कुटुंब कहा गया है। इसलिए वहां एक ओर मनुर्भव के माध्यम से नियम पालन युक्त मनुष्य बनने का संदेश है तो वहीं दूसरी ओर पुरोहित के माध्यम से ऐसे व्यक्ति अथवा नागरिक का आवाह्न मिलता है जो राष्ट्र को सदैव जीवंत और जागृत बनाए रखेंगे। क्या आज व्यक्ति निर्माण के लिए हमें वेदों की ओर लौटने की भी आवश्यकता नहीं है? आज जहां एक ओर कुछ लोग ज्ञान, विज्ञान, तकनीक आदि के माध्यम से राष्ट्रीय और वैश्विक फलक पर भारत को गौरवान्वित कर रहे हैं। तो वहीं कुछ लोग काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, स्वार्थ, आपसी वैमनस्य एवं आपराधिक प्रवृत्तियों में भी लिप्त हो रहे हैं। क्या इस प्रकार के व्यक्ति मानवता के कल्याण हेतु काम कर सकते हैं? अधिकांश नागरिक अधिकारों को लेकर तो समग्र रूप से सचेत हैं लेकिन नागरिक कर्तव्यों के पालन में पीछे रहते हैं। मारपीट, हत्या, चोरी, दुष्कर्म, जाति-संप्रदायगत आपसी वैमनस्य आदि शत्रुता को बढ़ावा देने वाले अपराधों में निरंतर वृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के विगत दिनों प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में देशभर में घृणा भाषण के अपराधों समेत विभिन्न समूह के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के लगभग 1500 मामले दर्ज किए गए। जो वर्ष 2021 के मुकाबले 31 प्रतिशत अधिक थे। बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। विगत दिनों के एक समाचार से यह भी सामने आया कि नगर निगम, विधानसभा और लोकसभा में चुनकर पहुंचे उम्मीदवारों में से अनेक पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। विगत लोकसभा चुनाव लड़ रहे 8,360 उम्मीदवारों में से 1,643 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज मिले हैं। क्या इस प्रकार के आपराधिक छवि वाले व्यक्ति समाज और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं?

जरा हटके

सुप्रीम कोर्ट ने...

डॉ. शैलेश शुक्ला

सफल लोकतंत्र की पहली शर्त है नागरिकों का जागरूक होना

लोकतंत्र केवल एक शासन प्रणाली नहीं बल्कि एक जीवंत सामाजिक अनुबंध है जिसमें राज्य की शक्ति अंततः नागरिकों की सहमति से संचालित होती है। संविधान, चुनाव, संसद और न्यायपालिका जैसी संस्थाएँ लोकतंत्र की संरचनात्मक रीढ़ अवश्य हैं, परंतु इन संस्थाओं की वास्तविक शक्ति और प्रभावशीलता नागरिकों की जागरूकता, सहभागिता और नैतिक प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। यदि नागरिक अपने अधिकारों, कर्तव्यों और शासन की प्रक्रियाओं के प्रति सजग नहीं होते, तो लोकतंत्र केवल कागज़ी ढाँचा बनकर रह जाता है। इसीलिए यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है जागरूक, शिक्षित और सक्रिय नागरिक समाज। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में यह तथ्य और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ लगभग 97.9 करोड़ से अधिक पंजीकृत मतदाता 2024 के आम चुनाव में मतदान के पात्र थे। चुनाव आयोग के आँकड़ों के अनुसार इस चुनाव में लगभग 64.64 करोड़ लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और कुल मतदान प्रतिशत लगभग 65.79 रहा। यह आँकड़ा एक ओर लोकतांत्रिक भागीदारी के बड़े स्तर को दर्शाता है, तो दूसरी ओर यह भी संकेत देता है कि अभी भी बड़ी संख्या में नागरिक मतदान प्रक्रिया से दूर रहते हैं। जब लगभग एक तिहाई योग्य मतदाता मतदान नहीं करते, तो यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या लोकतंत्र की नीतियाँ और निर्णय वास्तव में पूरी जनता की इच्छा को प्रतिबिंबित कर पा रहे हैं। जागरूक नागरिक केवल मतदान करने वाला व्यक्ति नहीं होता बल्कि वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में सक्रिय भूमिका निभाता है। वह राजनीतिक दलों के घोषणापत्रों को पढ़ता है, उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि को समझता है, नीतिगत मुद्दों पर विचार करता है और चुनाव के बाद भी सरकार की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखता है। लोकतंत्र में सरकार को पाँच वर्ष के लिए पूर्ण अधिकार नहीं दिया जाता, बल्कि यह अपेक्षा की जाती है कि नागरिक लगातार उसकी नीतियों और निर्णयों का मूल्यांकन करते रहें। यदि नागरिक इस निगरानी की भूमिका निभाना बंद कर दें, तो शासन तंत्र में जवाबदेही कमजोर पड़ जाती है और भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद तथा सत्ता के दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है। नागरिक जागरूकता का सीधा संबंध शिक्षा और सूचना तक पहुँच से है। जिस समाज में शिक्षा का स्तर ऊँचा होता है और स्वतंत्र तथा विश्वसनीय सूचना माध्यम उपलब्ध होते हैं, वहाँ नागरिक अधिक विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं। लोकतंत्र में मतदाता केवल संख्या नहीं, बल्कि सूचित मतदाता होना चाहिए। यदि नागरिक बिना तथ्यों की जाँच किए केवल भावनाओं, जातीय या धार्मिक पहचान के आधार पर मतदान करते हैं, तो लोकतंत्र की गुणवत्ता प्रभावित होती है। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों में यह पाया गया है कि जहाँ नागरिकों की राजनीतिक साक्षरता अधिक होती है, वहाँ सार्वजनिक नीतियाँ अधिक स्थिर और दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। भारत में नागरिक जागरूकता को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा समय-समय पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। स्कूलों, कॉलेजों और समुदाय स्तर पर मतदाता शिक्षा, जागरूकता अभियान और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिकों को मतदान के महत्व के बारे में बताया जाता है। इसके बावजूद, शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से शिक्षित वर्ग के बीच मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत कम देखा गया है। यह विडंबना इस बात की ओर संकेत करती है कि केवल औपचारिक शिक्षा पर्याप्त नहीं है; नागरिकता की चेतना और लोकतांत्रिक जिम्मेदारी का भाव भी उतना ही आवश्यक है जागरूक नागरिकों की उपस्थिति लोकतंत्र को केवल चुनाव तक सीमित नहीं रहने देती, बल्कि उसे सहभागी शासन में बदल देती है। सूचना का अधिकार अधिनियम, सामाजिक अंकेक्षण, जनहित याचिका और स्थानीय निकायों में भागीदारी जैसे उपकरण तभी प्रभावी हो सकते हैं जब नागरिक उनका प्रयोग करना जानते हों और करने का साहस रखते हों। भारत में सूचना का अधिकार कानून के माध्यम से लाखों लोगों ने सरकारी निर्णयों और खर्चों पर सवाल उठाए हैं, जिससे कई मामलों में भ्रष्टाचार उजागर हुआ और प्रशासनिक सुधार हुए। यह इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि जब नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सजग होते हैं, तो लोकतंत्र अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनता है। लोकतंत्र में मीडिया और नागरिक जागरूकता का भी गहरा संबंध है। स्वतंत्र और जिम्मेदार मीडिया नागरिकों तक सही और संतुलित जानकारी पहुँचाने का कार्य करता है, जबकि जागरूक नागरिक मीडिया के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं। डिजिटल युग में जहाँ सूचना का प्रवाह अत्यंत तेज हो गया है, वहीं भ्रामक सूचनाओं और फर्जी खबरों का प्रसार भी बढ़ा है। यदि नागरिक डिजिटल साक्षर नहीं होंगे और सूचना के स्रोतों की विश्वसनीयता की जाँच नहीं करेंगे, तो वे आसानी से दुष्प्रचार का शिकार बन सकते हैं। इससे लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया प्रभावित होती है और समाज में ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। एक सफल लोकतंत्र में नागरिक केवल अपने अधिकारों की ही नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों की भी उतनी ही समझ रखते हैं। संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और मतदान का अधिकार देता है, परंतु साथ ही उनसे यह अपेक्षा भी करता है कि वे कानून का पालन करें, करों का भुगतान करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और सामाजिक सद्भाव बनाए रखें। जब नागरिक केवल अधिकारों की माँग करते हैं, परंतु कर्तव्यों की अनदेखी करते हैं, तो लोकतंत्र का संतुलन बिगड़ जाता है। जागरूक नागरिक वह होता है जो इस संतुलन को समझता है और अपने आचरण में उसका पालन करता है।

पीसीबी ने गेंदबाज नसीम शाह पर लगाया जुर्माना

मुख्यमंत्री मरियम नवाज पर कमेंट किया था, बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन माना

- पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी और मरियम नवाज की यह फोटो 26 मार्च की है, जब पीएसएल के ओपनिंग डे पर दोनों स्टेडियम पहुंचे थे।

पीसीबी की तीन सदस्यीय अनुशासन समिति ने इस मामले में सुनवाई की। नसीम ने बिना शर्त माफी मांगी और अपने सोशल मीडिया मैनेजर को बर्खास्त कर दिया। पीसीबी ने न केवल नसीम पर भारी जुर्माना लगाया, बल्कि उनके मैनेजर को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अब वह मैनेजर पीसीबी के दायरे में आने वाले किसी भी अन्य खिलाड़ी के साथ काम नहीं कर पाएगा।

मुंबई, एजेंसी

पाकिस्तान क्रिकेट में एक बार फिर खेल और राजनीति का टकराव सामने आया है। पाकिस्तान के युवा तेज गेंदबाज नसीम शाह पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई एक विवादित ट्वीट के चलते की गई, जिसे बाद में उनके अकाउंट से हटा दिया गया था।जानकारी के मुताबिक, यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के पहले मैच के बाद एक संवेदनशील टिप्पणी सोशल मीडिया पर सामने आई। दरअसल, PCB ने इस सीजन के आयोजन को लेकर पहले ही घोषणा की थी कि टूर्नामेंट बिना दर्शकों के आयोजित किया जाएगा। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने यह फैसला ईंधन बचत और पश्चिम एशिया में चल रहे संकट को ध्यान में रखते हुए लिया था।हालांकि, इस फैसले के बावजूद मैच के दौरान मरियम नवाज, जो कि पंजाब की मुख्यमंत्री हैं और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी भी हैं, लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम पहुंचीं। उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात की और मैच का हिस्सा बनीं, जिससे PCB के पहले फैसले पर सवाल उठने लगे।इसी बीच नसीम शाह के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से PCB के एक पोस्ट को कोट करते हुए एक विवादित टिप्पणी की गई। इस ट्वीट में लिखा गया था, "उन्हें लॉर्ड्स की रानी की तरह ट्रीट क्यों किया जा रहा है?" यह टिप्पणी सीधे तौर पर मरियम नवाज की मौजूदगी पर सवाल उठाती नजर आई। हालांकि, कुछ ही देर में यह ट्वीट डिलीट कर दिया गया, लेकिन तब तक यह सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था।

नसीम ने मीडिया टीम की गलती बताई

विवादित ट्वीट के कुछ मिनट बाद ही उसे डिलीट कर दिया गया। इसके बाद नसीम ने एक और पोस्ट कर सफाई दी कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। सोमवार को उन्होंने एक नया बयान जारी कर कहा, 'मेरे अकाउंट से पिछला पोस्ट मेरी मैनेजमेंट टीम ने किया था, वह मेरे विचार नहीं हैं। मैं अपने प्लेटफॉर्म की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं और सोशल मीडिया मैनेजर को हटा दिया है। मैं इस गलती के लिए माफी मांगता हूं।'

पहले भी एक्शन हो चुका है

PCB इससे पहले भी खिलाड़ियों के राजनीतिक बयान पर सख्त कार्रवाई कर चुका है। पिछले साल आमेर जमाल पर भी एक नारे को लेकर 10 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया था। लेकिन नसीम शाह पर लगा जुर्माना उससे करीब 16 गुना ज्यादा है। मैं इस गलती के लिए माफी मांगता हूं।'

धोनी ने एआई स्टोरीटेलिंग प्लेटफॉर्म कुकू में निवेश किया

बोले- छोटे शहरों से निकले फाउंडर्स का विजन पसंद आया

मुंबई, एजेंसी

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने AI-ऑपरेटेड स्टोरीटेलिंग प्लेटफॉर्म कुकू (Kuku) में निवेश किया है। इसके साथ ही वे इसके शॉर्ट-फॉर्म वीडियो और ड्रामा एप कुकू TV के ब्रांड एंबेसडर भी बन गए हैं। धोनी का मानना है कि यह प्लेटफॉर्म भारत के साथ-साथ ग्लोबल ऑडियंस के लिए भी एक अलग तरह का एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस तैयार कर रहा है। धोनी ने कहा, 'मैंने कुकू में निवेश करने और कुकू TV का ब्रांड एंबेसडर बनने का फैसला इसलिए किया, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म दूसरों से अलग है। इन्होंने कई भाषाओं और फॉर्मेट्स में भारतीय दर्शकों के लिए एक बेहतरीन अनुभव तैयार किया है। प्लेटफॉर्म की ग्रोथ प्रभावित करने वाली है। सबसे बड़ी बात यह कि मैं इसके फाउंडर्स से जुड़ाव

महसूस करता हूं, क्योंकि वे भी मेरी तरह छोटे शहरों से आते हैं और उन्होंने इस लेवल का बिजनेस खड़ा किया है।' धोनी ने आगे कहा कि वे भारत के लिए बनाए जा रहे इस AI-ऑपरेटेड स्टोरीटेलिंग प्लेटफॉर्म के विजन पर भरोसा करते हैं। उनका मानना है कि यह तकनीक न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में मनोरंजन का तरीका बदल सकती है। कुकू के को-फाउंडर और COO विनोद कुमार मीणा ने बताया कि धोनी को साथ जोड़ना उनके लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा, 'हमारे थाला (धोनी) उन चुनिंदा हस्तियों में से हैं जिनकी पहुंच पूरे देश में है। चूंकि हम पूरे भारत के लिए कुकू बना रहे हैं, इसलिए वे हमारे लिए एकदम सही फिट हैं।' वहीं कंपनी के CTO विकास गोयल ने कहा कि धोनी को लोगों की गहरी समझ है। जब हम क्रिएटर्स और कंज्यूमर्स के लिए AI-बेस्ड स्टोरीटेलिंग स्टैक बना रहे हैं, तब धोनी का अनुभव और नजरिया हमारे लिए काफी कीमती साबित होगा। कुकू के को-फाउंडर और CEO लाल चंद बिसू ने कहा, 'धोनी अपने उन बोल्ड फैसलों के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें लेने में दूसरे लोग हिचकिचाते हैं। कुकू में हम भी इसी तरह के साहसी दांव लगा रहे हैं। धोनी की यह अनकंवेंशनल (लीक से हटकर) सोच हमारी कंपनी की वैल्यूज से मेल खाती है।'

फास्ट न्यूज

कॉमेडियन सुनील पाल की इवेंट में बेइज्जती

नई दिल्ली। मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। वीडियो एक इवेंट का है, जहां उन्हें गुलदस्ता देने के लिए मंच पर बुलाया गया और बाद में बेइज्जती कर उतरने को कहा गया। वायरल वीडियो मुंबई में हुए एक मुशायरे का है, जहां कुछ कवि मंच पर बैठे हैं। एक शख्स सुनील पाल को गुलदस्ता देने के लिए बुलाता है।

ट्रम्प के नाम पर होगा फ्लोरिडा एयरपोर्ट का नाम

वॉशिंगटन। अमेरिका के फ्लोरिडा में पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर राष्ट्रपति ट्रम्प के नाम पर रखने का फैसला लिया गया है। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डीसैंटिस ने सोमवार को एक बिल पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर 'प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे. ट्रम्प इंटरनेशनल एयरपोर्ट' किया जा रहा है। फ्लोरिडा सरकार के फैसले के बाद अब इस नाम को लागू करने के लिए फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) को औपचारिक प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके बाद फ्लाइट चार्ट, नेविगेशन सिस्टम और एयरपोर्ट साइनेज में बदलाव किया जाएगा। FAA की मंजूरी मिलने पर 1 जुलाई से यह नाम लागू हो सकता है। ऐसा होने पर ट्रम्प पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे, जिनके कार्यकाल के दौरान ही उनके नाम पर एयरपोर्ट रखा जाएगा।

टोल प्लाजा पर आज से नगद भुगतान नहीं होगा

नई दिल्ली। कल यानी 1 अप्रैल से देश के सभी टोल प्लाजा पर नगद भुगतान बंद हो जाएगा। वाहन चालक सिर्फ फास्टैग या UPI पेमेंट के जरिए ही टोल टैक्स चुका सकेंगे।

इसके अलावा, आज रात 12 बजे के बाद देश में टैक्स और बैंकिंग से जुड़े 3 बड़े कामों की डेडलाइन खत्म हो रही है। कल से टैक्स, रेलवे और बाजार से जुड़े 10 नियम भी बदल जाएंगे।

धुरंधर-2 के मेजर इकबाल अर्जुन रामपाल भावुक हुए

सक्सेस पर टीम को धन्यवाद दिया, कहा- सपने सच होते हैं

मुंबई, एजेंसी

रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर-2 ने 11 दिनों में कई रिकॉर्ड बनाए हैं। फिल्म 1365 करोड़ कलेक्शन के साथ बॉलीवुड की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग और इंडियन सिनेमा की पांचवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। फिल्म की सफलता से मेजर इकबाल का किरदार निभाने वाले अर्जुन रामपाल भावुक हो गए और उन्होंने टीम का धन्यवाद किया। अर्जुन रामपाल ने पहली फिल्म मोक्ष से अब तक की तस्वीरें शेयर कर सोशल मीडिया पर लिखा है, 'बचपन में काउबॉय बनने से लेकर धुरंधर तक मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि इस सफर में इतने लोग साथ रहे। मेरे प्यारे फैंस, साथ देने के लिए दिल से धन्यवाद।' आगे उन्होंने लिखा, 'धुरंधर की इस शानदार टीम का शुक्रिया, आप सब मेरे मजबूत

सहारा रहे। और मेरा "बब्बर शेर" रणवीर सिंह, तुम्हारा खास धन्यवाद। लोकेंद्र धर, ज्योति देशपांडे, श्वेता, कास्टिंग टीम, आर. माधवन, राकेश बेदी, संजय दत्त, प्रीति शील, स्मृति, आप सभी का आभार। यह लिस्ट और लंबी होगी। मैं बहुत खुश हूं। धैर्य, मेहनत और जुनून के साथ बने रहें, तो सपने सच होते हैं।' फिल्म 19 मार्च को रिलीज हुई और 11 दिनों में 1365 करोड़ कमा चुकी है।

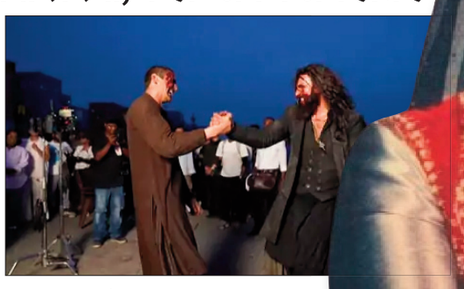

मीना कुमारी की 54वीं डेथ एनिवर्सरी

जन्म पर अनाथालय में छोड़ा, 4 साल में परिवार का सहारा बनीं, पति के असिस्टेंट ने थप्पड़ मारा

मुंबई, एजेंसी

मीना कुमारी की जिंदगी जितनी चमकदार पर्दे पर दिखी, उतनी ही दर्द और संघर्ष से भरी असलियत में रही। जन्म लेते ही पिता द्वारा अनाथालय की सीढ़ियों पर छोड़ दिए जाने से शुरू हुई उनकी कहानी ने महज चार साल की उम्र में ही उन्हें परिवार का सहारा बनने पर मजबूर कर दिया। आगे चलकर फिल्मी दुनिया में नाम कमाने के बावजूद उनका निजी जीवन तकलीफों से भरा रहा। 'बैजू बावरा', 'साहिब बीबी और गुलाम' और 'पाकीजा' जैसी फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से उन्होंने दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी। लेकिन पर्दे की इस चमक के पीछे उनकी जिंदगी दर्द, अकेलेपन और टूटे रिश्तों से घिरी रही। कमाल अमरोही के साथ रिश्तों में आई कड़वाहट और उनके सहायक द्वारा थप्पड़ मारने जैसी घटनाओं ने उनके भीतर के दर्द को और गहरा किया। यही पीड़ा उनके अभिनय में झलकी और उन्हें ट्रेजेडी क्वीन बना गई।

चार साल की उम्र में ही परिवार का सहारा बनीं

मीना कुमारी को फिल्मी करियर में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वे बचपन से ही पढ़ना चाहती थीं, लेकिन घर की हालत इतनी खराब थी कि चार साल की उम्र में उन्हें परिवार का पेट पालने के लिए फिल्मों में काम करना पड़ा। उनके माता-पिता उन्हें शूटिंग के लिए फिल्म स्टूडियो ले जाने लगे।

टैगोर खानदान से रहा है रिश्ता

मीना कुमारी के पिता, मास्टर अली बख्श, भेरा (अब पाकिस्तान) से आए एक सुन्नी मुस्लिम थे, जो रंगमंच के कलाकार, हारमोनियम वादक और उर्दू कवि थे। उनकी माता, इकबाल बेगम (मूल नाम प्रभावती देवी), उत्तर प्रदेश के मेरठ की थीं और बंगाली परिवार से संबंध रखती थीं। उन्होंने विवाह के बाद इस्लाम धर्म अपनाया। रवींद्रनाथ टैगोर के दूर के चचेरे रिश्तेदार की बेटी थीं।

बड़ी बहन खुर्शीद जूनियर और छोटी बहन महलीका (मधु), जो बाल कलाकार और अभिनेता महमूद की पत्नी थीं। जब महजबीं का जन्म हुआ, तब उनके पिता को डॉक्टर की फीस देने के पैसे नहीं थे।

फिलिस्तीनी अपराधियों को 90 दिन में फांसी

अपील करने का अधिकार खत्म, मंत्रियों ने संसद में शैंपेन खोल जश्न मनाया

- राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इत्तमार बेन ग्विर ने संसद में इस बिल का प्रस्ताव रखा था।
- इजराइली सांसदों ने ताली बजाकर कानून का स्वागत किया।

तेल अवीव, एजेंसी

इजराइल की संसद (नैसेट) ने सोमवार को फिलिस्तीनी अपराधियों को सजा देने वाला बिल पास कर दिया है। इसके तहत वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनियों को इजराइली नागरिकों की हत्या करने या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने पर सीधे मौत की सजा दी जा सकेगी। इसमें अपील का भी कोई अधिकार नहीं होगा। सजा सुनाए जाने के 90 दिनों के अंदर फांसी दी जाएगी। यह कानून राष्ट्रवादी या आतंकवादी इरादे से की गई हत्याओं पर लागू होगा। हालांकि, अदालत को विशेष कारणों के तहत उम्रकैद की सजा देने का भी अधिकार होगा। यह बिल राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इत्तमार बेन ग्विर ने

आगे बढ़ाया था। बिल पास होने के बाद बेन ग्विर और दूसरे सांसदों ने संसद में ही शैंपेन की बोतल खोलकर जश्न मनाया। उन्होंने कहा, "आज इजराइल खेल के नियम बदल रहा है, जो यहूदियों की हत्या करेगा, वह सांस नहीं ले सकेगा।" बेन ग्विर ने पहले धमकी दी थी कि अगर बिल पर वोट नहीं कराया गया तो उनकी पार्टी सरकार से समर्थन वापस ले लेगी। इसका नतीजा यह है कि एक ही इलाके में दो लोग एक ही तरह का अपराध करें, तो उन्हें अलग-अलग सजा दी जाएगी। इससे फिलिस्तीनियों के लिए मौत की सजा की आशंका बढ़ जाएगी। संगठनों ने इसे फिलिस्तीनियों को निशाना बनाने वाला और इजराइलियों को छूट देने वाला बताया। विपक्षी नेता यायर लापिद ने बिल की आलोचना करते हुए इसे हमास के सामने समर्पण बताया।

मानवाधिकार संगठनों ने इसे नस्लीय भेदभावपूर्ण और बदला लेने वाली नीति बताया है। इस बिल का विरोध करते हुए इजराइल के मानवाधिकार और नागरिक समाज संगठनों ने कहा कि यह कानून फिलिस्तीनियों के खिलाफ नस्लीय हिंसा को बढ़ावा देंगे।

इजराइल में फिलिस्तीनियों और इजराइली यहूदियों के लिए अलग कानून

इस बिल की मांग इजराइल के चरमपंथी दक्षिणपंथी गुट लंबे समय से करते आ रहे थे। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर मिलिट्री कानून लागू होता है। इस बिल के जरिए मिलिट्री कोर्ट के नियमों में बदलाव कर दिया गया है, जिससे अब जज बिना सर्वसम्मति के भी मौत की सजा सुना सकेंगे। दूसरी ओर, इजराइली यहूदी बस्ती निवासी जो वेस्ट बैंक में रहते हैं, उनपर इजराइली सिविलियन कानून लागू होता है। इसका मतलब है कि उनका मुकदमा सामान्य इजराइली नागरिक अदालतों में चलता है।

इजराइल में अब तक सिर्फ दो बार ही मौत की सजा दी गई

इजराइल के पूरे इतिहास में केवल दो बार ही मौत की सजा दी गई। पहला मामला 1948 के अरब-इजराइली युद्ध के दौरान का है। इजराइली सेना के कैप्टन मेयर टोबियान्स्की को जासूसी के आरोप में एक सैन्य अदालत में दोषी ठहराया गया और उसी दिन फायरिंग स्क्वाड से गोली मारकर सजा दी गई।

बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

बिल पास होने के तुरंत बाद इस बिल के खिलाफ इजराइल के सिविल राइट्स संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। साथ ही इसे असंवैधानिक बताते हुए खारिज करने की मांग की है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले इस बिल का विरोध किया था, लेकिन गाजा सीजफायर लागू होने के बाद उन्होंने अपना रुख बदल लिया और अंतिम वोट में इसका समर्थन किया।

अमेरिका की ईरान में घुसकर यूरेनियम जब्त करने की तैयारी

ट्रम्प 10 हजार एक्स्ट्रा सैनिक भेज रहे, अप्रैल तक जंग खत्म करना मकसद

तेहरान, एजेंसी

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ईरान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई करने का आदेश दे सकते हैं। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रम्प ईरान के पास मौजूद यूरेनियम को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। ईरान के पास करीब 400 किलो समृद्ध (एनरिच्ड) यूरेनियम है, जिसका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में किया जा सकता है। ट्रम्प ने अपने सहयोगियों से कहा है कि ईरान को यह यूरेनियम छोड़ना ही होगा। अगर बातचीत से बात नहीं बनी, तो इसे जबरदस्ती भी लिया जा सकता है। इस बीच, अमेरिका मिडिल ईस्ट में करीब 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने की योजना बना रहा है। इनमें से 3,500 से ज्यादा सैनिक पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। यूरेनियम एक ऐसा पदार्थ है, जिससे परमाणु ऊर्जा भी बनाई जा सकती है और परमाणु बम भी। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि उसे कितना एनरिच यानि कि शुद्ध किया गया है। माना जा रहा है कि

ईरान का बड़ा परमाणु भंडार उन पहाड़ी ठिकानों के मलबे के नीचे दबा है, जिन्हें अमेरिका ने बमबारी में निशाना बनाया था। IAEA प्रमुख राफेल ग्रोसी के मुताबिक, यह यूरेनियम इस्फहान की अंडरग्राउंड टनल और नतांज जैसे ठिकानों पर हो सकता है। ट्रम्प ने पहले दावा किया था कि हमलों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह तबाह हो गया, लेकिन अब माना जा रहा है कि काफी यूरेनियम नष्ट नहीं हुआ, बल्कि मलबे के नीचे दब गया है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि ज्यादातर यूरेनियम मलबे के नीचे दबा है और अभी उसे निकालने का कोई प्लान नहीं है। साथ ही, ईरान के पास अभी भी ऐसी मशीनें हैं।

बदलाव : स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स की ब्याज दरों में बदलाव नहीं, लगातार 9वीं तिमाही ब्याज दर स्थिर

सुकन्या में 8.2% और पीपीएफ पर 7.1% ब्याज मिलता रहेगा

नई दिल्ली, एजेंसी

नई दिल्ली से आई ताजा जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने अप्रैल से जून (Q1FY27) तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट (FD), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं।यह लगातार नौवीं तिमाही है जब सरकार ने इन योजनाओं के ब्याज दरों को यथावत बनाए रखा है। इससे पहले आखिरी बार दिसंबर 2023 में सरकार ने कुछ स्कीम्स की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की थी। उसके बाद से अब तक निवेशकों को किसी तरह का बदलाव

देखने को नहीं मिला है।स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स भारत में आम लोगों के लिए बचत का एक अहम जरिया मानी जाती हैं। खासतौर पर मध्यम वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इन योजनाओं में सुरक्षित निवेश के लिए भरोसा जताते हैं। इन योजनाओं में निवेश करने पर एक तय दर से ब्याज मिलता है, जिससे निवेशकों को जोखिम कम और रिटर्न स्थिर मिलता है।सरकार द्वारा ब्याज दरों को स्थिर रखने का फैसला ऐसे समय में आया है, जब महंगाई और बाजार की स्थिति को लेकर लगातार नजर रखी जा रही है। माना जा रहा है कि मौजूदा आर्थिक हालात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निवेशकों को स्थिरता देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है।वित्त विशेषज्ञों का कहना है कि ब्याज दरों में स्थिरता से उन निवेशकों को फायदा मिलता है, जो लंबे समय के लिए सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न चाहते हैं।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर 7.1% ब्याज दर

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) पर 7.1% और सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% ब्याज मिलता रहेगा। स्मॉल सेविंग्स स्कीमों पर ब्याज दरें 4% से 8.2% के बीच हैं। सरकार छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों पर फैसला लेने से पहले देश में कैश और महंगाई की स्थिति पर भी नजर रखती है। इनकी समीक्षा हर तीन महीने पर होती है।

ब्याज दरों का हर तिमाही में रिव्यू होता है

स्मॉल सेविंग्स स्कीम की ब्याज दरों का हर तिमाही में रिव्यू होता है। इनकी ब्याज दरें तय करने का फॉर्मूला श्यामला गोपीनाथ समिति ने दिया था। समिति ने सुझाव दिया था कि इन स्कीम की ब्याज दरें समान मैच्योरिटी वाले सरकारी बॉन्ड के यील्ड से 0.25-1.00% ज्यादा होनी चाहिए। सभी स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स से हुए कलेक्शन को नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड (NSSF) में जमा किया जाता है।

घरों तक जंग की आंच, दूध-किराना-इलाज महंगे होंगे

नई दिल्ली/मुंबई/भोपाल। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने कंपनियों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। कच्चे तेल और अन्य कच्चे माल की कीमतें बढ़ने से लागत बढ़ रही है और कंपनियां दाम बढ़ाने पर विचार कर रही हैं। इससे बोतलबंद पानी, नमक, तेल जैसी रोजमर्रा की चीजें, एसी, फ्रिज जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल से लेकर नॉन-सर्जिकल मेडिकल आइटम के दाम बढ़ सकते हैं। वजह यह है कि इस जंग ने प्लास्टिक उद्योग की रीढ़ तोड़ दी है। बीते 30 दिनों में कच्चे माल के दाम 50-70% तक बढ़ चुके हैं। सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाले प्लास्टिक दाने एलडीपीई के दाम 110 रु/ किलो से 180 रुपए तक पहुंच गए हैं। अन्य पॉलीमर और रॉ मटेरियल भी 30 हजार से 70 हजार रुपए प्रति टन तक वृद्धि हुई है। ऐसे में अप्रैल में प्लास्टिक की कीमतें 50-60% तक बढ़ सकती हैं। प्लास्टिक टंकी व कंटेनर के दाम 30-40% तक बढ़ने की आशंका है। ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुनील शाह कहते हैं कि प्लास्टिक इंडस्ट्री से 5 लाख लोग जुड़े हैं।

मुनाफे के चक्कर में ग्राहकों को भूली कंपनी

क्राफ्ट हाइंज को तोड़ने के बजाय सुधारेंगे नए सीईओ कैहिलेन, ग्राहकों की सेहत पर जोर

न्यूयॉर्क, एजेंसी

जब स्टीव कैहिलेन को क्राफ्ट हाइंज का सीईओ बनाया गया, तो काम साफ था- कंपनी को दो हिस्सों में तोड़ना। लेकिन महज छह हफ्ते के भीतर उन्होंने वह फैसला पलट दिया। उन्होंने बोर्ड को समझाया, वॉरेन बफे के उत्तराधिकारी ग्रेग एबेल को फोन किया और कहा, 'यह कंपनी ठीक हो सकती है, तोड़ने की जरूरत नहीं है।' यह कोई छोटा फैसला नहीं था। लगातार 9 तिमाहियों से घटती बिक्री, शेयर में गिरावट और उपभोक्ताओं का सस्ते ब्रांड्स की तरफ जाना, सब कुछ क्राफ्ट हाइंज के खिलाफ था। ऑस्कर मेयर, फिलाडेल्फिया क्रीच चीज, जेल-ओ, कूल-एड जैसे दशकों पुराने ब्रांड्स की पहचान तो है, लेकिन जैसा कैहिलेन खुद कहते हैं, 'लोग टी-शर्ट खरीदना चाहते हैं, प्रोडक्ट नहीं। हमें दोनों बिकवाने हैं।' 60 साल के कैहिलेन फूड इंडस्ट्री के पुराने खिलाड़ी हैं। इससे पहले वो केलॉग कंपनी को दो हिस्सों में बांट चुके थे। स्नैक्स वाला हिस्सा केलानोवा बना और मार्स ने उसे 36 अरब डॉलर (अभी के हिसाब से 3.4 लाख करोड़ रुपए) में

खरीद लिया। यानी कंपनी तोड़ने का अनुभव उनके पास था, लेकिन इस बार उन्होंने वो नहीं किया जो उनसे उम्मीद थी। उनका तर्क सीधा था- अगर अभी तोड़ा, तो दोनों हिस्से कमजोर निकलेंगे। पहले कंपनी को मजबूत करो, फिर विकल्प खुले रहेंगे। चुनौतियां कम नहीं हैं। वजन घटाने वाली दवाओं ने लोगों की खाने की आदतें बदल दी हैं। अमेरिका में 'अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड' पर राजनैतिक बहस छिड़ी है। ईरान युद्ध से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जो सप्लाई चेन को प्रभावित कर सकती हैं। कैहिलेन मानते हैं कि बीते 10 वर्षों में कंपनी ने उपभोक्ताओं को नजर-अंदाज किया और सिर्फ मुनाफे पर ध्यान दिया। यही सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन कैहिलेन आश्वस्त नजर आते हैं।35,000 कर्मचारियों को नई दिशा दी गई है। रिसर्च टीमें प्रोटीन-रिच विकल्पों पर काम कर रही हैं। आर्टिफिशियल कलर और सामग्री हटाने की प्रक्रिया पहले से चल रही थी। कैहिलेन की मां आयरलैंड से थीं और चार बच्चे पालते हुए कॉलेज की डिग्री ली थी। संभवतः यही जिद्द उन्हें विरासत में मिली है। क्राफ्ट हाइंज दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी फूड एंड बेवरेज कंपनी है। वॉरेन बफे की फर्म बर्कशयर हैथवे और निवेश फर्म 3जी कैपिटल ने 2015 में हाइंज और क्राफ्ट फूड्स का विलय कराया था। कंपनी के पोर्टफोलियो में ऑस्कर मेयर, फिलाडेल्फिया क्रीच चीज, जेल-ओ, कूल-एड, कैप्री सन और हाइंज केचअप समेत दर्जनों ब्रांड हैं। कंपनी के दुनियाभर में 35,000 कर्मचारी हैं और इसका मुख्यालय शिकागो में है। ग्रेग एबेल जो अब बर्कशयर हैथवे के सीईओ हैं, उन्होंने भी कैहिलेन के साथ ही 1 जनवरी को ही नई जिम्मेदारी संभाली है।

अंडे पर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी जाएगी

अफसर बोले- नए नियम से रेट बढ़ेंगे, रोज डेढ़ करोड़ अंडे दूसरे राज्यों से आते हैं

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। यूपी में अंडों पर फिलहाल एक्सपायरी डेट नहीं लिखी जा सकेगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग (FSDA) ने हाथ खड़े कर दिए हैं। FSDA का कहना है- अगर ये नियम सख्ती से लागू होते हैं, तो यूपी में अंडों की शॉर्टेज आ जाएगी। रेट भी काफी बढ़ जाएंगे। वहीं, यूपी कुक्कुट विकास समिति के अध्यक्ष वीपी सिंह कहते हैं- विभाग बड़े व्यापारियों के दबाव में है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि यूपी सरकार के इस आदेश को लागू करने में असली अड़चन क्या है? किसे नुकसान है? यूपी में अंडा किन राज्यों से आता है? उन राज्यों में क्या नियम लागू हैं? जहां तक खुले बाजार में बिकने वाले अंडों और स्टोरेज के अंडों की पहचान का सवाल है। इसके लिए सुझाव दिया गया था कि दोनों के लिए अलग-अलग इंक का इस्तेमाल किया जाए। जो अंडे कोल्ड स्टोर में जाने वाले हैं, उन पर ग्रे स्याही से स्टैंपिंग की जाए।

वीपी सिंह का कहना है- केंद्र सरकार ने फरवरी, 2023 में यह नियम बनाया था। अगर विभाग की इसे लागू करने की मंशा होती तो वो संबंधित राज्यों से भी कह सकता था कि जिस तरह एक्सपोर्ट किए जा रहे अंडों पर स्टैंपिंग की जाती है, उसी तरह यूपी में सप्लाई होने वाले अंडों पर भी की जाए।

आरोप- बड़े व्यापारी के दबाव में नहीं लागू हो पा रहा आदेश

यूपी कुक्कुट विकास समिति के अध्यक्ष वीपी सिंह कहते हैं- विभाग बहानेबाजी कर रहा है। ये लोग यूपी के बड़े व्यापारियों के दबाव में हैं। पशुपालन विभाग की ओर से जो आंकड़े सप्लाई और उत्पादन के दिए गए हैं, वो आंकड़े 2012 के हैं। यूपी में अंडों का उत्पादन काफी बढ़ चुका है।

बड़े व्यापारी और एनईसीसी को क्या फायदा

वीपी सिंह बताते हैं- बड़े व्यापारी और खासकर एनईसीसी (नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी) अंडों की कालाबाजारी करने के लिए इस तरह का आदेश लागू नहीं होने दे रही।

2 वजह से नियम लागू नहीं हो पा रहे

पहली वजह- दूसरे राज्यों ने नहीं आ पाएंगे अंडे

यूपी में हर दिन लोग 3.35 करोड़ अंडे खा जाते हैं। ये आंकड़े यूपी को सबसे ज्यादा खपत वाला राज्य बनाते हैं। यूपी के पोल्ट्री फार्मों में 1.80 करोड़ अंडों का प्रोडक्शन होता है। बाकी अंडे हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से आते हैं। इन 5 राज्यों से यूपी में रोज करीब 1.55 करोड़ अंडों की सप्लाई होती है। यह कुल खपत का 46% है।

दरअसल, इन 5 राज्यों में अंडों पर स्टैंपिंग सिर्फ उन अंडों पर होती है, जिन्हें विदेश में एक्सपोर्ट करना होता है। यूपी में आने वाले अंडों पर कोई स्टैंपिंग नहीं होती। ऐसे में यूपी में अंडे पर प्रोडक्शन और एक्सपायरी डेट लिखने के नियम लागू होते ही दूसरे राज्यों के अंडे मार्केट में बिक नहीं पाएंगे। इससे तय है कि पूरे यूपी में अंडे की शॉर्टेज हो जाएगी।

दूसरी वजह- मार्केट और कोल्ड स्टोरेज में रखने वाले अंडों में कंफ्यूजन

यह भी बताया जा रहा है कि अंडे को अगर 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाए, तो इसे 35 से 45 दिनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखने पर यही अंडे 14 दिनों तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

कुशीनगर से विश्व शांति का संदेश, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2026 का भव्य शुभारंभ

कुशीनगर में तीन दिवसीय (31 मार्च से 2 अप्रैल) बौद्ध सम्मेलन का आयोजन

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ/कुशीनगर। कुशीनगर के महापरिनिर्वाण स्थल से विश्व शांति का संदेश देने वाला 'अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2026' मंगलवार से शुरू हो गया। 31 मार्च से 2 अप्रैल तक चलने वाले इस तीन दिवसीय आयोजन में देश-विदेश से आए बौद्ध भिक्षु, संत, विद्वान, नीति-निर्माता और युवा एक मंच पर जुटे हैं। सम्मेलन में भगवान बुद्ध की करुणा, शांति और शिक्षाप्रद संदेशों की वर्तमान

वैश्विक परिदृश्य में प्रासंगिकता पर गहन मंथन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 'वर्तमान समय में जब दुनिया के अनेक हिस्सों में संघर्ष और अनिश्चितता का माहौल है, ऐसे समय में भगवान बुद्ध के जीवन संदेश सकारात्मक मार्ग प्रशस्त करते हैं। उन्होंने बताया कि कुशीनगर में आयोजित यह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन वैश्विक स्तर पर शांति, सहअस्तित्व और आपसी समझ को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल है।' कुशीनगर के महापरिनिर्वाण मंदिर में 31 मार्च को अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का शुभारंभ मंत्रोच्चार के साथ हुआ।

स्मार्ट मीटर से कटा बिजली कनेक्शन 2 घंटे में जुड़ेगा

लखनऊ। लखनऊ में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (MVVNL) की एमडी रिया केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने स्मार्ट मीटर और वर्टिकल व्यवस्था में हो रहे कामों के बारे में बताया। उनका कहना है कि स्मार्ट मीटर पर अगर बिजली कनेक्शन कट जाता है तो बिजली बिल जमा करने के दो घंटे के अंदर कनेक्शन दोबारा से जोड़ दिया जाएगा। बिल निगेटिव में जाने पर 3 दिन का ही ग्रेस पीरियड रहेगा। स्मार्ट मीटर पर रीडिंग को लेकर आ रही समस्याओं पर उन्होंने कहा कि मध्यांचल की तरफ से 69 हजार चेक मीटर विभाग की तरफ से लगाया गया है,लेकिन एक भी मीटर में कोई डिफरेंस नहीं आया है।

फास्ट न्यूज

एअर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग

लखनऊ। लखनऊ में एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सोमवार शाम फ्लाइट पश्चिम बंगाल के बागडोगरा से दिल्ली जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक, फ्लाइट यूपी के अंबेडकरनगर के ऊपर थी, तभी पायलट के केबिन में धुआं महसूस हुआ। उस समय विमान 36 हजार फीट की ऊंचाई पर था। पायलट ने धुआं महसूस होते ही लखनऊ एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे कॉल किया।

मेट्रो स्टेशन पर कारतूस के साथ पकड़ा गया युवक

लखनऊ। लखनऊ में आईटी चौराहा मेट्रो स्टेशन पर एक युवक कारतूस लेकर पहुंच गया। सेक्योरिटी चेकिंग के दौरान उसके बैग में .315 बोर का कारतूस मिला। युवक की पहचान लखीमपुर खीरी के हाथीपुर कोठार के अनंतेश्वर वर्मा के रूप में हुई। उसके पास असलहे का लाइसेंस नहीं था। स्टेशन पर तैनात सेक्योरिटी गार्ड ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। घटना मंगलवार दोपहर करीब 1:24 बजे की है। स्टेशन पर एक्स-रे स्कैनिंग के दौरान बैग में कारतूस जैसा दिखा। शक होने पर सुरक्षा स्टाफ ने बैग खोलकर जांच की, तो एक कारतूस मिला। सूचना पर पहुंची महानगर थाना पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। पुलिस ने बरामद कारतूस को कब्जे में लेकर सील किया और आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मेट्रो प्रशासन से घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों का विवरण मांगा गया है।

एमबीए स्टूडेंट की किडनी निकालकर बेची

कानपुर। कानपुर में पुलिस ने अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का सोमवार देर रात खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक, एक एमबीए छात्र की किडनी 10 लाख रुपए में खरीदी गई और मरीज को 60 लाख रुपए में बेची गई। तय सौदे के अनुसार छात्र को 50 हजार रुपए कम दिए गए। इसके बाद उसने पुलिस को फोन कर मामले की जानकारी दी।

तेजी से रौंदते हुए निकला, दो बार पलटते हुए उलटा हो गया गोवंश, खाना छोड़ा

गली में बैठे बछड़े पर चढ़ाई कार

- कुचले जाने के बाद बछड़ा बेहोश हो गया। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं रह गई।
- सामने के घर से निकली महिला ने बछड़े को उठाने की कोशिश की।

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ के बीकेटी इलाके में गली में बैठे बछड़े पर युवक ने वरना कार चढ़ा दी। इसकी CCTV फुटेज सामने आई है। युवक ने अपने दरवाजे पर कार बैक की। घुमाते हुए बछड़े को तेजी से रौंदते हुए निकल गया। पहले अगले फिर पिछले पहिये से रौंद जाने पर बछड़ा दो बार पलटते हुए उलटा हो गया। वहीं पर बेहोश हो गया। मोहल्ले के लोगों ने बेहोश पड़े बछड़े को उठाने की कोशिश की लेकिन उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। इसके बाद लोगों ने पशु चिकित्सक को बुलाकर उसका इलाज कराया। करीब 4 घंटे बाद बछड़े को होश आया, लेकिन उसके पैर और पेट में अंदरूनी चोट आ गई है। वह चल-फिर नहीं पा रहा है। उसने खाना-पीना छोड़ दिया है। बढ़ी हुई स्पीड में बछड़े के ऊपर चढ़ती हुई गाड़ी निकल जाती है। इस दौरान बछड़े का पूरा शरीर दो बार बेलन जैसे घूमकर पलट जाता है।

1:13 मिनट की सीसीटीवी फुटेज में कुचलता दिखा

घटना की CCTV फुटेज सामने आई है। 1 मिनट 13 सेकंड के वीडियो में शुरू के 48 सेकंड तक आरोपी गली में गाड़ी बैक करता रहा। जब गाड़ी दरवाजे से मूव हुई थी तो उसमें आरोपी के अलावा एक व्यक्ति आकर और बैठा था लेकिन उसने गली में बैठे गोवंश को हटाया नहीं था। 49वें सेकंड में गाड़ी जैसे ही सीधी होती है, स्पीड बढ़ जाती है।

दोस्त से मिलने आया था, लौटते समय कार चढ़ाई

घटना रैथा रोड स्थित पूरम कॉलोनी की सोमवार सुबह की है। बछड़े के कुचले जाने के बाद मोहल्ले के लोगों ने गो-रक्षा दल के कार्यकर्ता सुधांशु रावत को सूचना दी। रावत और अन्य कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर घायल बछड़े के इलाज के लिए पशु चिकित्सक को बुलाया। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों के इलाज के बाद बछड़ा करीब चार घंटे बाद होश में आया। इस बीच, CCTV फुटेज खंगालने पर आरोपी की पहचान जानकीपुरम के डंडैया के फैजान अली के रूप में हुई। फैजान अपने दोस्त ज्ञानेंद्र से मिलने आया था। लौटते समय उसने बछड़े पर कार चढ़ाई।

बीकेटी थाना प्रभारी संजय सिंह ने कहा- बछड़े को जानबूझकर गाड़ी से कुचलने की शिकायत मिली है। गाड़ी नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। इस बीच, सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर आरोपी की पहचान जानकीपुरम के डंडैया के फैजान अली के रूप में हुई। फैजान अपने दोस्त ज्ञानेंद्र से मिलने आया था। लौटते समय उसने बछड़े पर कार चढ़ाई।

2 क्विंटल गांजा बरामद, तस्कर गिरफ्तार

लखनऊ। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में एसटीएफ ने ट्रक से 2 क्विंटल गांजा बरामद किया है। गांजे की कीमत करीब 52 लाख बताई जा रही है। टीम ने तस्कर ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। अपर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार सिंह ने बताया कि एसटीएफ को पिछले कुछ दिनों से कई राज्यों से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचना मिल रही थी। टीम तस्करों की तलाश में लगी थी। इस दौरान टीम को सूचना मिली कि ओडिशा से गांजा लदा ट्रक (नंबर JH-05 CX-4295) सुलतानपुर रोड के रास्ते लखनऊ आएगा और एचसीएल के पास सर्विस लेन में सुनसान जगह पर माल उतारा जाएगा। इस पर एसटीएफ टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और ट्रेलर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान ट्रक में बनी गुप्त कैविटी से 200 किलो गांजा बरामद हुआ। जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 52 लाख रुपए है। इसके बाद चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। चालक की पहचान नालंदा बिहार निवासी अजीत कुमार के रूप में हुई।

चीता-तेंदुआ के अंगों की तस्करी में 6 दोषी

लखनऊ सीबीआई कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। सीबीआई की जांच में सामने आए एक बड़े वन्यजीव तस्करी मामले में लखनऊ की CBI कोर्ट ने छह आरोपियों को दोषी करार दिया है। चीता और तेंदुए के अंगों की अवैध तस्करी से जुड़े इस मामले में अदालत ने सभी दोषियों को दो-दो साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया है, जिससे वन्यजीव अपराध के खिलाफ सख्त संदेश गया है। लखनऊ CBI कोर्ट ने मुमताज अहमद, जैबुन निशा, अजीज उल्लाह, वहीद, सरताज और मजीद को दोषी करार दिया। अदालत ने सभी छह आरोपियों को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने माना कि आरोपी संगठित तरीके से वन्यजीव तस्करी के अवैध नेटवर्क का हिस्सा थे। मामले की जांच के दौरान CBI ने आरोपियों के

ठिकानों पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित वन्यजीव के अंग बरामद किए थे। बरामद सामग्री में 18,000 तेंदुए के नाखून, 74 तेंदुए की खाल, 4 बाघ की खाल और बाघ-तेंदुए की हड्डियां शामिल थीं। ये सभी वस्तुएं अत्यंत संवेदनशील श्रेणी में आती हैं और इनका व्यापार पूरी तरह प्रतिबंधित है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह के वन्यजीव अंगों की तस्करी अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के जरिए की जाती है, जो एक संगठित अपराध का रूप ले चुकी है।

कान पकड़कर उठक-बैठक करने वाले आईएएस का इस्तीफा

यूपी में रिंकू सिंह 8 महीने से साइडलाइन थे; कहा- सैलरी मिली, लेकिन काम नहीं

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। यूपी के IAS अफसर रिंकू सिंह राही ने मंगलवार को नौकरी से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने लेटर में आरोप लगाया कि संवैधानिक व्यवस्था के समानांतर (पैरलल) एक अलग सिस्टम चल रहा है। उन्हें वेतन मिल रहा था, लेकिन जनसेवा का मौका नहीं मिल रहा था। हालांकि, रिंकू सिंह ने इस्तीफे को नैतिक निर्णय बताया। रिंकू को 8 महीने पहले शाहजहांपुर से हटाकर राजस्व परिषद भेजा गया था। तब से उन्हें फील्ड में कोई पोस्टिंग नहीं मिली थी। उस वक्त रिंकू सिंह पुवायां तहसील के SDM थे। उन्होंने खुले में शौच करने पर एक मुंशी से उठक-बैठक कराई थी। वकीलों ने इसका विरोध किया, तो रिंकू नरम पड़ गए थे। इसके बाद उन्होंने खुद उठक-बैठक लगाई थी। वीडियो सामने आने के बाद

उन्हें हटा दिया गया था। 44 साल के रिंकू सिंह राही 2021 बैच के IAS अफसर हैं। अभी उनकी 16 साल की नौकरी बची थी। बसपा शासन में 26 मार्च, 2009 को रिंकू सिंह पर फायरिंग हुई थी। जिसमें उन्हें सात गोलियां लगी थीं। इनमें से दो उनके चेहरे पर लगी थीं, जिससे उनका चेहरा बिगड़ गया था। 8 महीने पहले रिंकू सिंह राही मथुरा में जॉइंट मजिस्ट्रेट थे। वहां से ट्रांसफर होकर 24 जुलाई, 2025 को दोपहर 2 बजे पुवायां SDM का चार्ज संभाला था। इसी दौरान उनकी नजर परिसर के अंदर ही दीवार के पास टॉयलेट कर रहे वकील आज्ञाराम के मुंशी विजय (38) पर पड़ी। उन्होंने उसे टोक दिया और शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए कहा। मुंशी ने रिंकू सिंह को जवाब दिया कि शौचालय गंदे हैं। इस पर एसडीएम बिफर गए थे। कहने लगे थे कि ये गलती तहसील कर्मचारियों की है। उन्होंने मौके पर ही मुंशी से उठक-बैठक लगवा दी थी। तहसील परिसर में वकील अपनी कुछ मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तभी उनको ये बात पता चल गई। वकील भड़क गए। उन्होंने एसडीएम को मौके पर बुलवा लिया। एसडीएम मौके पर पहुंचे और कहने लगे कि मुंशी ने गलती की है, जिस पर वकीलों ने कहा कि गलती है, तो उठक बैठक लगवाना सही नहीं है। क्या आप उठक बैठक लगा सकते हैं? इस पर उन्होंने कहा, इसमें कोई शर्म नहीं है, मैं उठक बैठक लगा सकता हूं। इसके बाद उन्होंने 5 बार उठक-बैठक लगाई।

घटना : मुजफ्फरनगर में बहन को ईदी देने पर पत्नी से हुआ था झगड़ा

पति ने पत्नी, 2 बच्चों की हत्या करके जान दी

- इरशाद ने कुछ दिन पहले ही यह सेल्फी अपने बच्चों के साथ ली थी।
- यह नूरीन है, जिसका अपने पति इरशाद से करीब 10 दिन से झगड़ा चल रहा था।

तमसा संकेत, एजेंसी

मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में एक ही परिवार के 4 लोगों के शव एक कमरे में मिले हैं। कमरा अंदर से बंद था। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो पति फंदे पर लटका मिला। पत्नी जमीन और दोनों बच्चे फर्श पर पड़े थे। बेटा 2 साल का और बेटी 1 महीने की थी। घरवालों ने बताया कि पति-पत्नी के बीच ईद के दूसरे दिन (22 मार्च) से झगड़ा चल रहा था। पति ने अपनी बहन को ईदी में 1700 रुपए दे दिए थे। इससे पत्नी नाराज हो गई थी। मंगलवार तड़के 4 बजे तक भी

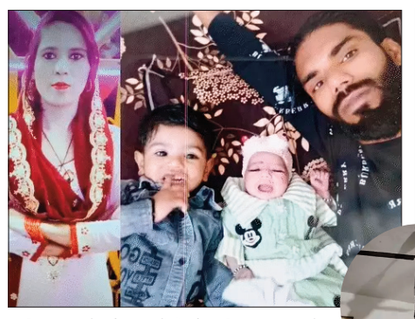

इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होता रहा। इसके बाद सुबह पति-पत्नी और दोनों बच्चों की लाशें कमरे में मिलीं। दोनों की 5 साल पहले शादी हुई थी। SSP संजय कुमार वर्मा ने बताया- शुरुआती जांच में सामने आया है कि पति ने पहले पत्नी और बच्चों की हत्या की, फिर आत्महत्या कर ली। मंगलवार सुबह काफी देर तक घर का दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों को शक हुआ। उन्होंने परिवार के एक रिश्तेदार को बुलाया और पुलिस की मौजूदगी में दरवाजा खोला गया। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। सरवट इलाके की गली नंबर-6 इरशाद (32), पत्नी नूरीन (28), दो साल के बेटे आहिल और एक महीने की बेटी अक्शा के साथ रहता था। इरशाद पेंटिंग का काम करता था। मंगलवार सुबह जब काफी देर तक इरशाद के घर का दरवाजा नहीं खुला, तो पड़ोसियों ने उसके भाई नौशाद को बुलाया। नौशाद जब अंदर पहुंचा, तो इरशाद, उसकी पत्नी और दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। नौशाद ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। एक साथ चार लोगों की बॉडी मिले की खबर पर सिविल लाइन थाना प्रभारी आशुतोष कुमार फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद SSP संजय कुमार वर्मा, ASP सिद्धार्थ के. मिश्रा, CO मंडी राजू कुमार साव, डॉग स्क्वायड, एलआईयू और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की। नूरीन की बहन अर्शी ने बताया- मेरी बहन की शादी के 22 दिन बाद से ही जीजा उसको प्रताड़ित करने लगे थे।

पड़ोसियों और रिश्तेदारों से हुई पूछताछ

पुलिस ने घटना की कड़ियां जोड़ने के लिए पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछताछ की। अफसरों का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घरवालों ने पुलिस को बताया कि हाल ही में इरशाद की बहन घर आई थी, जिसे उसने ईदी के रूप में 1700 रुपए दे दिए थे। इसी बात को लेकर उसकी पत्नी नूरीन नाराज हो गई थी। दोनों के बीच इस बात को लेकर झगड़ा भी हुआ था। नूरीन ने अपने मायके पक्ष को भी इसके बारे में बताया था।

पृष्ठ 01 का शेष...

ईसी ऑफिस के ...

ममता ने X पर एक पोस्ट में कहा- भाजपा के एजेंटों को बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस में हजारों फर्जी फॉर्म 6 आवेदन जमा करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। यह वोटर हाइजैकिंग की कोशिश है। भाजपा ने केरलम के मेनिफेस्टो में AIIMS और तिरुवनंतपुरम से कन्नूर तक हाई-स्पीड रेलवे नेटवर्क विकसित करने का वादा किया। पार्टी ने 'भक्ष्य आरोग्य सुरक्षा कार्ड' योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500, बुजुर्गों, विधवाओं और जरूरतमंद महिलाओं को 3000 पेंशन देने की घोषणा की। भाजपा ने असम के लिए मेनिफेस्टो में लव जिहाद पर एक्शन, घुसपैठियों से कब्जाई जमीन वापस लेने, राज्य में UCC लागू करने, युवाओं को 5 साल में 2 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। पत्र में कुल 31 वादे किए गए हैं। असम के लिए कांग्रेस ने 5 गारंटियां जारी की हैं। इसमें महिलाओं को नकद सहायता, सीनियर सिटिजन को पेंशन, हर परिवार को 25 लाख तक का हेल्थ कवर, गायक जुबीन गर्ग को 100 दिन में न्याय और 10 लाख स्वदेशी लोगों को जमीन का अधिकार देने का वादा शामिल है। TVK चीफ विजय और उनकी पार्टी के 5 हजार कार्यकर्ताओं पर चुनाव के नियमों के उल्लंघन के आरोप में आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज हुआ। TMC के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश और बिहार से अवैध रूप से वोटर बंगाल के विभिन्न जिलों में लाए जा रहे हैं। बिहार के 800 वोटरों को मेदिनीपुर में जोड़ा गया है। भाजपा बंगाल की जनसांख्यिकी बदलना चाहती है।

कांग्रेस अफवाह ...

कि भारत सेमीकंडक्टर सेक्टर का नया हब बनेगा।' पीएम मोदी ने गांधीनगर में सम्राट सम्प्रति म्यूजियम में राष्ट्रीय संत पूज्य आचार्य पद्मसागर सूरीश्वरजी का आशीर्वाद भी लिया। इस म्यूजियम में सात अलग-अलग विंग हैं, जहां दुर्लभ जैन चट्टानों, पत्थर और धातु की मूर्तियां, प्राचीन पांडुलिपियां, सिक्के, चांदी के रथ और मिनिएचर पेंटिंग प्रदर्शित की गई हैं। म्यूजियम में दो हजार से ज्यादा दुर्लभ चीजें रखी गई हैं, जो जैन धर्म के विकास और उसके सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाती हैं। पीएम मोदी ने शाम करीब 5 बजे वाव-थराड पहुंचे, वहां उन्होंने 20 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें बिजली, रेलवे, सड़क परिवहन, स्वास्थ्य, शहरी विकास, आदिवासी विकास और ग्रामीण विकास से जुड़े कार्य शामिल हैं। पीएम 5100 करोड़ रुपए की लागत वाले अहमदाबाद-धोलेरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इसके अलावा इदार-बडोली बाइपास के फोर लेन निर्माण और NH-754K के धोलेवीरा-मौवाना-वाव-सांतलपुर सेक्शन का शिलान्यास भी किया।

उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि दुश्मन देश 'फेक या झूठे हमले'करके गलत जानकारी फैला सकते हैं। इससे पहले, तुर्किये के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि NATO ने ईरान की तरफ से दागी गई एक नई मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि ईरान जंग राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की शर्तों पर खत्म होगी। अमेरिका इसी दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि होर्मुज जैसे समुद्री रास्ते की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ अमेरिका की नहीं है, बल्कि दूसरे देशों को भी इसमें साथ देना चाहिए। उन्होंने NATO पर आरोप लगाया कि जब अमेरिका ने मदद मांगी थी, तब कई देशों ने साथ नहीं दिया और उल्टा अमेरिका की आलोचना की। ईरान से जुड़ा मामला सुलझने के बाद NATO से जुड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका यह सुनिश्चित करेगा कि होर्मुज स्ट्रेट खुला रहे। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि कुछ सहयोगी देशों ने अमेरिका को अपने हवाई क्षेत्र और सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी है, ऐसे में नाटो की व्यवस्था पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है।

भारत समेत ...

भारत का ज्यादातर इंटरनेशनल इंटरनेट बैंडविड्थ अरब सागर और खाड़ी क्षेत्र से होकर आता है। लेटेंसी बढ़ जाएगीः अगर केबल्स को नुकसान होता है, तो ट्रैफिक को लंबे 'पैसिफिक रूट' पर डायवर्ट करना पड़ेगा। इससे लेटेंसी यानी डेटा ट्रैवल टाइम बढ़ जाएगा। इंटरनेट स्लो होगाः यूट्यूब, इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बफरिंग बढ़ जाएगी। वीडियो कॉल और क्लाउड सर्विस में भी दिक्कतें आ सकती हैं। भारत का IT और आउटसोर्सिंग सेक्टर करीब 250 बिलियन डॉलर (23.48 लाख करोड़) का है।

सीएम योगी की मां को अपशब्द कहने वाला मौलाना गिरफ्तार

बिहार के विधायक बोले- यूपी एसटीएफ मेरे सामने ले गई

तमसा संकेत, एजेंसी

बिहार। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ की मां के खिलाफ भड़काऊ बयान देने वाले मौलाना अब्दुल सालिम चतुर्वेदी को STF ने गिरफ्तार किया है। मौलाना बिहार में अररिया के जोकीहाट का रहने वाला है। यूपी STF ने उसे वहीं से दबोचा है। बिहार में अमौर सीट से AIMIM विधायक अख्तरुल ईमान ने सोमवार को मौलाना की गिरफ्तारी की पुष्टि की। मौलाना सालिम भी AIMIM से जुड़ा रहा है। विधायक ने बताया, मौलाना को उनके ही विधानसभा क्षेत्र से पकड़ा गया है। विधायक ने बताया, हमें खबर मिली है कि मौलाना को कुछ लोग उठाकर ले गए, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि मौलाना को किडनैप किया गया है या गिरफ्तार। उन्होंने इस मामले को लेकर जिले के SP को जानकारी दी है। दरअसल, अब्दुल्ल सलीम पर रमजान के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के खिलाफ अभद्र

टिप्पणी करने का आरोप है। 6 मार्च को वीडियो सामने आया था। इसके बाद यूपी में हिंदूवादी संगठन और भाजपा के लोगों ने उनपर कार्रवाई करने की मांग की थी। बलरामपुर में केस भी दर्ज हुआ था। अख्तरुल ईमान ने कहा, "सोमवार देर शाम मौलाना को पूर्णिया जिले के दलमालपुर चौक से कुछ लोग उठाकर ले गए। अब उनकी किडनैपिंग हुई है या यूपी STF ने उठाया है, मुझे पता नहीं। इस मामले को लेकर जब मैंने जिले के थाना प्रभारी से बात की तो उन्होंने मुझे यूपी STF से बात कराया। STF ने बताया कि उन्हें कानूनी प्रकिया के तहत पुलिस अपने साथ ले गई है।"

तमसा संकेत
tamsa.newslko@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक विद्या देवी द्वारा कृष्णा डाइनेस्टी प्रिंटिंग प्रेस म0 न0 195 सेक्टर 6-बी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड लखनऊ-226 029 (उ0प्र0) से मुद्रित व प्रकाशित।

सम्पादक : विद्यादेवी

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा

समाचार पत्र में प्रकाशित लेख, राजनीतिक विश्लेषण, लेखकों के अपने विचार हैं। सम्पादक का इन विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं हैं।
मो0- 9415799533
R.N.I. NO. UPHIN/2021/83676